



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 3, 2019/आश्विन 11, 1941

No. 318]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 3, 2019/ ASVINA 11, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2019

अंतिम जांच परिणाम

विषय: बंगलादेश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये पटसन उत्पादों अर्थात् पटसन यार्न/ ट्वाइन (बहु परत वाले/ केबल किया हुआ और एकल) हैसियन फेब्रिक और पटसन यार्न के आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्क जैसा कि दिनांक 02.07.2018 को किये गये मैसर्स अजीज फाइबर्स लिमि. (उत्पादक/ निर्यातक), बांग्लादेश द्वारा अनुरोध किया गया है, के संबंध में सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 के नियम 22 के अंतर्गत नई शिपर समीक्षा।

फा. सं. 7/25/2018-डी जी ए डी .— सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है (इसके पश्चात अधिनियम के रूप में भी संदर्भित) तथा उसके सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 जिसे समय समय पर संशोधित किया गया (इसके पश्चात "नियमावली के रूप में भी संदर्भित") के संबंध;

क. मामले की पृष्ठभूमि

- जबकि, मूल पाटनरोधी जांच में, निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके पश्चात प्राधिकारी के रूप में भी संदर्भित) ने अन्य बातों के साथ साथ दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/19/2015 – डी जी ए डी के

संदर्भ में सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 69 के अंतर्गत आने वाले बंगलादेश के मूल के अथवा से निर्यात किये गये "पटसन उत्पादों" अर्थात् पटसन यार्न/ ट्वाइन (बहुपरत वाले/ केवल किया हुआ और एकल), हैसियन फेब्रिक और पटसन सेकिंग थैले के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की। केंद्र सरकार ने दिनांक 05 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 01/2017 – सीमा शुल्क (ए डी डी) – सीमा शुल्क तथा दिनांक 03 अप्रैल, 2017 के सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 11/2017 – सीमा शुल्क (ए डी डी) के संदर्भ में निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को अधिसूचित किया।

3. मैसर्स अजीज फाइबर्स लिमि. (उत्पादक/ निर्यातक) बांगलादेश सीमा प्रशुल्क अधिनियम के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के संबंध में नई शिपर समीक्षा (एन एस आर) के लिए एक आवेदन दायर किया जिसमें बंगला देश के मूल के अथवा वहां निर्यात किये गये "पटसन यार्न/ ट्वाइन (बहुपरत वाला/ केवल किया हुआ और एकल) और पटसन सेकिंग थैले" जिसमें दिनांक 03 अप्रैल, 2017 के सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 11/2017 – सीमा शुल्क (ए डी डी) के संदर्भ में "पटसन उत्पादों" पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है, के आयातों के संबंध में अलग अलग पाटन मार्जिन का दावा करते हुए नई शिपर समीक्षा (एन एस आर) का अनुरोध किया गया है।
4. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों से प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर मैसर्स अजीज फाइबर्स लिमि. (उत्पादक/ निर्यातक) के संबंध में बंगला देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये "पटसन यार्न/ ट्वाइन (बहुपरत वाला/ केवल किया हुआ और एकल) और पटसन सेकिंग थैले" के पाटित आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्कों के अधिरोपण के उद्देश्यों से अलग अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए दिनांक 02 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या 7/25/2018 – डी जी ए डी के संदर्भ में नई शिपर समीक्षा जांच शुरू की।
5. वित्त मंत्रालय ने दिनांक 24 अगस्त, 2018 के अधिसूचना सं. 42/2018 – सीमा शुल्क (ए डी डी) के संदर्भ में उपर्युक्त एन एस आर जांच के पूरा होने तक मैसर्स अजीज फाइबर्स लिमि. (उत्पादक/ निर्यातक) द्वारा किये गये संबद्ध वस्तुओं के सभी निर्यातों पर अनंतिम आकलन को अधिसूचित किया।
6. इस नई शिपर समीक्षा के उद्देश्य से जांच की अवधि 1 जुलाई, 2018 से 31 मार्च, 2019 के रूप में निर्धारित की गयी थी।

ख. प्रक्रिया

7. नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन वर्तमान जांच के संबंध में किया गया है :
 - (i) प्राधिकारी ने संबद्ध एन एस आर पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 2 जुलाई, 2018 की अधिसूचना सं. 7/25/2018 – डी जी ए डी के संदर्भ में एक आम सूचना जारी की।
 - (ii) प्राधिकारी ने आवेदक को निर्यातक की प्रश्नावली की एक प्रति के साथ साथ जांच शुरुआत से संबंधी अधिसूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें जांच की अवधि के समाप्त होने के बाद निर्धारित प्रश्नावली में सभी संगत आंकड़े प्रस्तुत करने और लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अवसर दिया।
 - (iii) प्राधिकारी ने भारत में बंगलादेश उच्चायोग को जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भी अग्रेषित की।
 - (iv) प्राधिकारी ने भारत में ज्ञात घरेलू उत्पादकों को जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें अपने विचार लिखित रूप में अवगत कराने के लिए अवसर दिया।

- (v) जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर, प्रश्नावली का उत्तर मैसर्स अजीज फाइबर्स लिमि. (उत्पादक/ निर्यातक) बांग्लादेश, एन. एस. आर. द्वारा प्रस्तुत किया गया था, भारत में "पटसन उत्पादों" के घरेलू उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में आई. जे. एम. ए. ने भी अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किये थे।
- (vi) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुरोधों/ सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।
- (vii) प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार मौखिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने के लिए और उसके बाद लिखित अनुरोधों द्वारा सूचना प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान करने के लिए दिनांक 8 जुलाई, 2019 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये विचारों/ सूचना के संबद्ध में खंडन संबंधी उत्तर प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त अनुरोधों पर उपयुक्त रूप से विचार किया है।
- (viii) इस जांच की अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये सभी संगत अनुरोधों/ टिप्पणियों पर विचार किया गया है और उन्हें इस प्रकटन विवरण में शामिल किया गया है।
- (ix) प्राधिकारी ने प्रतिभागी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 30 अगस्त, 2019 को एक प्रकटन विवरण जारी किया।
- (x) विवरण में *** ए. डी. नियमावली के अंतर्गत, गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई और प्राधिकारी द्वारा ऐसी ही समझी गई सूचना को प्रस्तुत करता है।
- (xi) पी. ओ. आई. के लिए 71.92 रूपए प्रति अमरीकी डॉलर की विनिमय दर अपनाई गई है।

ग. विचाराधीन उत्पाद

8. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद 'पटसन उत्पाद' है जिसमें पटसन यार्न/ ट्वाइन (बहुपरत वाला/ केबल किया हुआ और एकल), हैसियन फेब्रिक और और पटसन सेकिंग थैले शामिल हैं। प्राधिकारी ने उत्पादकों को मूल जांच में प्रत्येक प्रकार के पटसन उत्पादों के लिए अलग अलग शुल्क की सिफारिश की थी। यह जांच मूल जांच में यथा परिभाषित पी. यू. सी. के निर्यातों से संबंधित है, जैसाकि जांच शुरुआत अधिसूचना में कहा गया है।
9. वर्तमान जांच इस अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उनके द्वारा दायर किये गये आवेदन के अनुसार मैसर्स अजीज फाइबर्स लिमि. (उत्पादक/ निर्यातक) द्वारा पटसन यार्न/ ट्वाइन (बहुपरत वाला/ केबल किया हुआ और एकल) (दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 के अंतिम जांच परिणामों में यथाउल्लिखित विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत उत्पाद प्रकारों) के प्रस्तावित निर्यातों से संबंधित है।

घ. विभिन्न अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

10. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध :

- i. आई जे एम ए यह अनुरोध करता है कि आवेदक ने प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("ए डी ए") के नई शिपर समीक्षाओं जो पिछले पांच वर्ष में लागू रही हैं और नई शिपर समीक्षा के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी और सेस्टेट के निर्णयों के संबंध में निदेशालय की समग्र के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन के संबंध में अधिनियम पाटनरोधी नियमावली और करार, इस अधिनियम के संबंध में पर्याप्त और आवश्यक सूचना प्रदान किये बिना वर्तमान जांच शुरुआत की मांग की है।

- ii. इसके अलावा, आज की तारीख तक इस याचिका में यह “दर्शाने” के लिए किसी सूचना और साक्ष्य का अभाव है कि आवेदक नियम 22 की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और इस कारण से वर्तमान जांच को तत्काल समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- iii. जबकि एक विश्वसनीय नई शिपर का यह अधिकार है कि वह अलग अलग मार्जिन की मांग करे उसके साथ ही निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात का पता लगाने की आवश्यकता है कि यह दावे विश्वसनीय हैं और पाटनरोधी शुल्कों का कोई दुरुपयोग/ हानि / प्रवंचना नहीं किया गया है। यह इस कारण से है कि आवेदक को इस तथ्य को कठोरता से सिद्ध करने की आवश्यकता है कि (क) वे असली/ विश्वसनीय निर्यातक हैं जिन्होंने विश्वसनीय बिक्री की है (ख) उन्होंने मूल जांच में वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है (ग) वे संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक अथवा निर्यातक जिन पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा है, से संबंधित नहीं हैं। वर्तमान मामले में आवेदक उनमें से किसी मानदंड को पूरा नहीं करता है।
- iv. आवेदन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है। जैसा कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा एच एंड आर जॉनसन (इण्डिया) लिमि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माना गया है कि “दर्शाना” शब्द का आशय आवेदक द्वारा केवल इस अभिकथन की औपचारिकता मात्र का निर्धारण करना नहीं है कि आवेदक “संबंधित” नहीं हैं।
- v. आवेदक ने यह साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि वे निर्यात करने वाले देश में से किसी भी निर्यातक/ उत्पादक से संबंधित नहीं है जो इस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन हैं, उसे सिद्ध करने के लिए साक्ष्य की बात ही छोड़ दी जाये। इस कानून के अंतर्गत अपेक्षा “दर्शाने के लिए” अर्थात्, “यह प्रदर्शित करने के लिए” और न कि “दावा” करने अथवा “उल्लेख” करने के लिए है।
- vi. वेब रिसर्च दर्शाती है कि उक्त आवेदक ऐसे समूह से संबंधित हैं जो संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में संलग्न हैं। ऐसे बहुत से अन्य पक्षकार हैं। ये पक्षकार दशकों से अस्तित्व में हैं।
- vii. आवेदकों ने जांच की अवधि अर्थात् वह अवधि जो नियम 22 के अंतर्गत जांच की शुरुआत की बाद की अवधि है के रूप में बाद की अवधि की मांग की। टाइल्स मामले में जिसमें भावी समीक्षा अवधि की अवधारणा की बहुत अधिक आलोचना की गई, में माननीय सेस्टेट द्वारा निर्णय का संदर्भ लिया जाता है।
- viii. जांच की भावी अवधि के कारण, आवेदक (क) केवल औपचारिक निर्यात अर्थात् 90 मी. ट. निर्यात (ख) कृत्रिम रूप से बहुत अधिक कीमत पर कीमत में हेर फेर और उसमें बदलाव करने में सक्षम हुए हैं। यहां यह नोट प्रासंगिक है कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के बावजूद, बंगला देश से आयात काफी अधिक मात्रा में हुआ है। हालांकि निर्यातक ने कम मात्रा में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने का विकल्प अपनाया है जो कुल आयातों की तुलना में बहुत कम है। आवेदक के आचार से यह पता चलता है कि वे वर्तमान मामले के भविष्य के बारे में गंभीर नहीं हैं और वर्तमान प्रयास केवल भाग्य अजमाने के लिए प्रयास करना भर है, यदि उन्हें अनुकूल मार्जिन मिले। उनकी कार्यवाही यह नहीं दर्शाती है कि वे अपने उत्पादों का निर्यात करने के बारे में गंभीर हैं।
- ix. आवेदक ने भारत में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री का रद्द न किये जाने योग्य संविदागत करारों के साक्ष्य के संबंध में सही रूप से उत्तर नहीं दिया है।
- x. एक नई शिपर समीक्षा में जांच की अवधि के दौरान आवेदकों द्वारा किये गये निर्यात उचित मात्रा में विश्वसनीय वाणिज्यिक लेन देन होना चाहिए और पाटन मार्जिन के लिए आधार कीमत होना चाहिए। यह देखे जाने की आवश्यकता है कि क्या विचाराधीन बिक्री प्रकारात्मक है और यह नई शिपर की भविष्य में की जाने वाली बिक्री

- का द्योतक होगा। यदि किसी उत्पादक अथवा निर्यातक के लेन देन में कीमत मात्रा और समग्र परिस्थितियां जिन पर उन बिक्री की वाणिज्यिक व्यावहारिकता पर विचार किये जाने की आवश्यकता है, शामिल हो तब मूल्य और मात्रा दोनों के मामले में उन बिक्री की वास्तविकता की जांच की जानी चाहिए।
- xi. अन्य देश के कानूनों जैसे यू एस, ब्राजील, कनाडा, यूरोपीय संघ, तुर्की, ताइवान और वियतनाम आदि के कानूनों को नोट करना इस संबंध में प्रासंगिक है जो यह प्रावधान भी करता है कि निर्यातक द्वारा किया गया लेन देन विश्वसनीय और वाणिज्यिक प्रकृति के होने चाहिए।
 - xii. प्राधिकारी ने विशेष रूप से यह निर्धारित किया गया है कि निर्यातक द्वारा निर्यात की गई मात्राएं वाणिज्यिक मात्रा के रूप में होनी चाहिए जिससे कि पाटन का अलग अलग मार्जिन प्राप्त हो सके। आवेदक ने यह तर्क दिया है कि व्यापार संबंधी सूचना हाल में ही जारी की गई है और इस प्रकार से इसके भविष्य मामलों पर प्रभाव पड़ेगा, यह अनुरोध किया गया है कि दर्शाया गया सिद्धांत एक नया सिद्धांत नहीं है। वास्तविक निर्यात का सिद्धांत वाणिज्यिक मात्रा में किया गया है और इसकी पहचान प्राधिकारी द्वारा तथा माननीय सेस्टेट द्वारा विगत में की गयी है।
 - xiii. यदि किसी निर्यातक को केवल निर्यात की लघु मात्रा अथवा निर्यातों की प्रत्याशा के आधार पर मार्जिन की अनुमति दी जाती है तब इससे अपेक्षाकृत कम मार्जिन प्राप्त करने के लिए निर्यातक द्वारा कीमतों में हेर फेर करने की गुंजाइश बनी रहेगी।
 - xiv. विचाराधीन उत्पाद के आयातकों से प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, यह इस तथ्य को दबाने के लिए जांच बूझकर किये गये प्रयास की शंका को बल देता है कि एक सांकेतिक निर्यात कम अथवा शून्य पाटन मार्जिन प्राप्त करने के उद्देश्य से अवास्तविक कीमत पर किया गया था और उसके पश्चात आक्रामक रूप से इन मात्राओं का पाटन किया गया था।
 - xv. आवेदकों ने घरेलू उद्योग से सूचना को छिपाने और घरेलू उद्योग को अपने हितों का बचाव करने से रोकने के एकमात्र उद्देश्य से और बिना किसी सही कारण के अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
 - xvi. आवेदकों ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि किस प्रकार से उनके द्वारा दावा किये गये निर्यात कीमत तर्कसंगत, विश्वसनीय, सांकेतिक है और किस प्रकार से यह निर्यात कीमत के निर्धारण के उद्देश्य से पर्याप्त है।
 - xvii. भारत में हुए आयातों की तुलना निर्यात कीमत की विश्वसनीयता को दर्शाने के लिए नहीं की जा सकती है।
 - xviii. सूचना और साक्ष्य की समुचितता और पर्याप्तता को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकारों के उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमत और उत्पादन की लागत दोनों के संबंध में पूर्ण रूप से सूचना अपूर्ण प्रतीत होती है और न ही निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास उत्पाद प्रकारों में अंतरों को सिद्ध करने के लिए रिकार्ड पर कोई सूचना उपलब्ध है।
 - xix. यदि प्राधिकारी बिना किसी पक्षपात के यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आवेदक उस शर्त को पूरा करता है और अलग अलग शुल्क न्यायोचित है, तब यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदक को मूल जांच में नमूने में शामिल न की गई सहयोगी कंपनियों को देखते हुए भारित औसत शुल्क दिया जा सकता है क्योंकि मूल जांच में नमूना शामिल था।
 - xx. घरेलू उद्योग इस कारण से भी अतिरिक्त रूप से चिंतित हैं कि घरेलू उद्योग के पास यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि बंगला देश के निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराया गया साक्ष्य और सूचना की गणवत्ता और मात्रा सभी विगत जांचों में हमेशा एक प्रमुख मुद्दा रहे हैं।

11. आवेदक उत्पादक/ निर्यातक द्वारा अनुरोध :

- i. आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 में यथानिर्धारित एक नई शिपर के रूप में माने जाने के लिए अपेक्षाओं को पूरा करता है जिसका आधार विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 में है। नियम 22 यह कहता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रश्नगत निर्यातक देश में किसी निर्यातक अथवा उत्पादक जिन्होंने जांच की अवधि के दौरान भारत में किसी उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, के लिए पाटन के अलग अलग मार्जिन का निर्धारण के उद्देश्य से एक आवधिक समीक्षा करेगा बशर्ते कि ये निर्यातक अथवा उत्पादक यह दर्शाते हैं कि ये निर्यातक देश में किसी निर्यातक अथवा उत्पादक जो इस उत्पाद के पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन हैं से संबंधित नहीं हैं। आवेदक इन अपेक्षाओं को पूरा करता है।
- ii. यह दोहराया जाता है कि वर्तमान एन एस आर जांच में आवेदक ने मूल जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया और न ही वे संबंधित हैं और साथ ही या तो नियमावली में यथानिर्धारित अथवा प्रशासनिक व्यापार सूचनाओं के माध्यम से यथा अधिसूचित एन एस आर के संदर्भ संबंध में उनमें यथा अधिसूचित संबद्ध वस्तुओं पर लगने वाले पाटनरोधी शुल्क के किसी उत्पादक अथवा निर्यातक से 'संबद्ध' के अन्य सभी आशय पर बल दिया गया है।
- iii. नियम 22 की शर्तों की पुष्टि करने के लिए अनुरोध और समानन के अलावा आवेदक ने विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जो कंपनी द्वारा संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की आरंभ तिथि को व्यौरा और समानन, लेखा परीक्षित रिपोर्ट और अन्य सांविधिक समानन, संयंत्र और उपस्करों आदि की खरीद का व्यौरा शामिल करता है जो आगे नई शिपर आवेदक के दावे को सिद्ध करेगा।
- iv. आवेदक नियम 22 की अपेक्षाओं को पूर्ण से पूरा करता है और उसके आगे यह अनुरोध करता है कि इन पक्षकारों का भारत में सामग्री को पाटित करने कोई उद्देश्य नहीं है और यह बहुत आवश्यक है कि उनके द्वारा किये गये वास्तविक निर्यातों के तथ्यों के आधार पर अलग अलग मार्जिन के निर्धारण के लिए नई शिपर समीक्षा को उनके वास्तविक निर्यातों को अध्यक्षीन किया जाये। आवेदक ने निर्धारित जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं का बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किया है। मैसर्स अजीज फाइबर्स लिमि. (उत्पादक/ निर्यातक), बांग्लादेश के मामले में, विचाराधीन उत्पाद का निर्यात 450 से 550 मी. ट. तक हुआ था।
- v. एन एस आर जांच पाटनरोधी करार तथा भारतीय पाटनरोधी नियमावली का अभिन्न हिस्सा है और यह प्रावधान किसी उत्पादक अथवा निर्यातक को एक नये निर्यातक के रूप में अपने मामले को सिद्ध करने के लिए उसमें यथानिर्धारित होने में सक्षम बनाता है जो प्राधिकारी को इस तथ्य की जांच करने में सक्षम बनायेगा कि क्या ऐसे नये निर्यातक द्वारा निर्यातों के मामले में पाटन का कोई कारक है। एन एस आर के विरुद्ध आई जे एम ए के आरोप का कोई आधार नहीं है।
- vi. न तो करार और न ही नियमावली किसी एन एस आर में अलग अलग मार्जिन के निर्धारण के लिए एक शर्त के रूप में निर्यात की किसी विशिष्ट मात्रा अथवा कीमत का निर्धारण करता है। असंबंधित नई शिपर 'नया' को बनाना सही रूप में इस तथ्य के कारण हुआ है कि मूल जांच की अवधि के दौरान इसने इस प्रक्षेत्र में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया जहां संबद्ध वस्तु पाटनरोधी जांच के अध्यक्षीन थे।
- vii. वास्तव में विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय निकाय ने स्पष्ट रूप से पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 के अनुसार समीक्षा किये जाने में मात्रा की आवश्यकताओं को निर्धारित करते हुए बनाये गये किसी कानून के विरुद्ध माना और इस संबंध में चावल पर मेक्सिको – पाटनरोधी शुल्क में विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय का निर्णय जी एम एक्सपोर्ट मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के साथ पठित भारतीय प्राधिकार पर बाध्यकारी है।

- viii. विगत कुछ मामलों में, प्राधिकारी ने नये निर्यातक को अलग अलग मार्जिन दिये जाने से इनकार किया है क्योंकि प्राधिकारी ने नये निर्यातक द्वारा निर्यातों की मात्रा को आवेदक उत्पादक/ निर्यातक को अलग अलग पाटन मार्जिन देने के लिए अपनाई जाने वाली वाणिज्यिक रूप से प्रतिनिधि मात्रा के रूप में विचार किये जाने के लिए बहुत कम पाया। हालांकि, वर्तमान मामला यह दर्शाता है कि वर्तमान मामले में मात्रा बहुत अधिक है और इस प्रकार की बहुत अधिक मात्रा से संबंधित निर्यात कीमत को सहज ढंग से विश्वसनीय के रूप में माने जाने की आवश्यकता है।
- ix. वर्तमान मामले में नये शिपर नियम 22 के अनुसार सभी मूल शर्तों और मात्रा की तर्कसंगतता तथा कीमत की विश्वसनीयता, दोनों की आवश्यकता के मामले में विगत हाल में प्राधिकारी द्वारा प्रथाओं के भाग के रूप में जारी किये जाने वाले अतिरिक्त शर्तों को भी पूरा करता है।
- x. आई जे एम ए द्वारा यह तर्क दिया गया है कि कोई भी अलग अलग मार्जिन का निर्धारण यहां नये शिपर के लिए नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में यह मूल मामले में यथा पाये गये 'निर्यातकों का नमूना नहीं लिया गया श्रेणी' पर लागू मार्जिन से छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता है। यह नियम स्पष्ट रूप से यह कहता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी निर्यातक अथवा उत्पादक के लिए अलग अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के उद्देश्य से एक आवधिक समीक्षा करेगा। प्राधिकारी द्वारा मेलामाइन के संबंध में अंतिम जांच परिणामों को प्रकाशित करते समय विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी भी एन एस आर में नमूना न लिये गये श्रेणी के लिए मार्जिन को अपनाने हेतु अपने इस निर्णय के बारे में स्पष्ट किया गया है कि यह 'आवेदक को पाटनरोधी शुल्क की नमूना न ली गई श्रेणी का दर्जा देने के लिए निर्णय लिया था, के संबंध में इस मामले के तथ्यों के द्वारा सीमित था।'
- xi. इस प्रकार के बाध्यकारी परिदृश्यों के अंतर्गत अपनाया गया कोई दृष्टिकोण नियम 22 में दी गई स्पष्ट कानूनी स्थिति जिसमें प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वह अपने संगत आंकड़ों के आधार पर नई शिप्परो के लिए अलग अलग मार्जिन का निर्धारण करे, में स्पष्ट कानूनी स्थिति को देखते हुए एक नियम नहीं बन सकता है।
- xii. आई जे एम ए का यह तर्क कि वर्तमान एन एस आर नियम 22 की शर्त को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्यों के बिना शुरू किया गया था, का इनकार इसलिए किया जाता है कि इसमें कोई आधार नहीं है। इस याचिका में यह दर्शाने के लिए साक्ष्य निहित था कि नई शिपर ने मूल जांच अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया और नई शिपर किसी उत्पादन अथवा निर्यातक से संबंधित नहीं है जिस पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा हो। इसके साथ ही तब से बहुत समय बीत चुका है जब से वर्तमान मामले की जांच शुरू की गई है और घरेलू उद्योग इन आवेदकों के दावे का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।
- xiii. भावी जांच की अवधि के होने के कारण आई जे एम ए के तर्क का कोई आधार नहीं है। टाइल्स मामले जिसमें जांच की अवधि बाद की अवधि के रूप में निर्धारित थी के बाद शुरू की गई और समाप्त की गई एन एस आर की पर्याप्त संख्या रही है। बाद की जांच की अवधि की प्रथा नियम 22 के प्रावधानों को देखते हुए सही है जो यह कहता है कि केंद्र सरकार इस नियमावली के उप नियम (1) में यथासंदर्भित समीक्षा की अवधि के दौरान ऐसे निर्यातकों अथवा उत्पादकों से आयातों पर अधिनियम की धारा 9क के उप धारा (1) के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्कों को नहीं लगायेगा और यदि नई शिपर को एन एस आर को आरंभ किये जाने के पूर्व निर्यात करना हो तब यह नियमावली व्यावहारिक उद्देश्य पूरा नहीं करेगी।
- xiv. आई जे एम ए द्वारा यह तर्क दिया गया है कि बाद की जांच की अवधि के कारण से आवेदक (क) केवल औपचारिक निर्यात करने अर्थात् 90 मी. ट. निर्यात (ख) कृत्रिम रूप से उच्च कीमत पर इस कीमत में हेर फेर

- करने और इसे गलत तरीके से पेश करने में सक्षम हुए हैं। इस तर्क का कोई आधार नहीं है। यहां आवेदक ने संबद्ध वस्तु का लगभग 450 – 550 मी. ट. (और न कि 90 मी. ट. जैसा कि तर्क दिया गया है) का निर्यात किया है जो बहुत अधिक मात्रा है और इस प्रकार की पर्याप्त मात्रा संभव नहीं हो सकती थी यदि कीमत में हेर फेर न किया गया होता जैसा कि आरोप लगाया गया है।
- xv. आई जे एम ए द्वारा यह तर्क दिया गया है कि भारत में निर्यात करने के लिए कोई प्रतिबंधता नहीं है यह दर्शाता है कि निर्यातक गंभीर नहीं है। इस तर्क का कोई आधार नहीं है। ऐसे संविदात्मक करार अनिवार्य नहीं हैं और ऐसे करार व्यापार के अवसरों पर निर्भर करते हैं। किसी भी मामले में, निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का लगभग 450 – 550 मी. ट. निर्यात किया है जो बहुत अधिक मात्रा है।
- xvi. आई जे एम ए द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एन एस आर समीक्षा में निर्यात विश्वसनीय वाणिज्यिक लेन देन होना चाहिए। यह नोट किया जा सकता है कि वर्तमान मामले में नई शिपर ने अलग अलग मार्जिन का निर्धारण करने के लिए बहुत अधिक मात्रा का निर्यात किया है। यह हमारे अनुरोध के प्रति बिना किसी पक्षपात के है कि मेक्सिको – राइस मामले में विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय ने स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी है कि प्राधिकारी पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 के तत्वाधान में नई शिपर समीक्षा आयोजित करने में मात्रा से संबंधित किसी आवश्यकताओं को अधिरोपित नहीं कर सकते हैं जो भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 का आधार है। हालांकि, वर्तमान मामले में निर्यातों की मात्रा निश्चित रूप से निर्यातों की तर्कसंगतता की जांच करने के लिए प्राधिकारी द्वारा लागू किये गये कुछ मानदंडों को पूरा करता है जैसा कि हाल के कुछ एन एस आर जांच परिणामों में स्पष्ट है।
- xvii. आई जे एम ए द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातकों से प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और आवेदकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। दोनों तर्कों का कोई आधार नहीं है। वर्तमान मामले में आयातक आवेदक के संबंधित पक्षकार नहीं हैं और किसी भी प्रकार से निर्यातक ने आयातक के प्रश्नावली के उत्तर को उन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए यह कार्य कर सकता था। आवेदक ने इस नियमावली में यथा अनुमत्य गोपनीयता का दावा किया है। वास्तव में इन पक्षकारों ने वास्तविक निर्यातों की सीमा भी दी है जिससे कि घरेलू उद्योग को वर्तमान मामले की बेहतर समझ हो सके।
- xviii. आई जे एम ए द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदकों ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये हैं कि किस प्रकार उनके द्वारा दावा की गयी निर्यात कीमत तर्कसंगत, विश्वसनीय है। इस तर्क का कोई कानूनी अथवा तथ्यात्मक आधार नहीं है। बात यह रह जाती है कि आवेदक ने भारत में बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किया है जो अपने आप में कीमत की तर्कसंगतता को प्रमाणित करता है। ऐसा कोई निर्यात कृत्रिम रूप से बढ़ायी गई कीमत पर किया जाना संभव नहीं हो सकता था।
- xix. आई जे एम ए द्वारा यह तर्क दिया गया है कि संबंधित आयातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को सहयोग नहीं किया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी इस सूचना का सत्यापन नहीं कर सकते हैं और अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं कि निर्यातक और आयातक के बीच कोई क्षतिपूर्ति संबंधी व्यवस्था नहीं है। इस तर्क का कोई आधार नहीं है। ऐसे कई मामले हैं जिसमें प्राधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि जहां आयातकों ने सहयोग नहीं किया लेकिन निर्यातकों द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत का सत्यापन किया गया था और स्वीकार किया गया था। आयातक द्वारा असहयोग किसी भी प्रकार से निर्यातक द्वारा दावा की गई कीमत की विश्वसनीयता को हानि नहीं पहुंचाती है और अन्य तंत्र है जिनका उपयोग उसका सत्यापन करने के लिए किया जा सकता है जैसे सीमा शुल्क/ डी जी सी आई एंड ए आदि के आंकड़े।
- xx. आई जे एम ए द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू बिक्री कीमत और विभिन्न प्रकार के उत्पादन की लागत दोनों के संबंध में संपूर्ण रूप से अपूर्ण सूचना प्रतीत होती है और न ही निर्दिष्ट प्राधिकारी के उत्पाद प्रकारों में

अंतर्गत्त का उल्लेख करने के लिए रिकार्ड पर कोई सूचना है। इस तर्क का कोई आधार नहीं है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में सभी लागू उत्पाद प्रकार से संबंधित सूचना है।

- xxi. आई जे एम ए द्वारा यह तर्क दिया गया है कि बंगला देश के निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य और सूचना की मात्रा हमेशा से सभी पिछली जांचों में एक प्रमुख मुद्दा रहा है। ऐसे अभिकथनों का कोई आधार नहीं है। यह महसूस किया जाता है कि प्राधिकारी ऐसी जांच को शुरू करता है और उसे पूरा करता है जब ऐसी जांच के लिए मामला स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो और न केवल उसके बारे में आरोप लगाया गया हो।

ड.. प्राधिकारी द्वारा जांच

12. पाटनरोधी नियमावली का नियम 22 में नीचे दिए गए अनुसार प्रावधान हैं :

22. ऐसे निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन जिनकी मूल रूप से जाँच नहीं की गई थी –

- (1) यदि किसी उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी संबंधित निर्यातक देश के किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक, जिसने जांच की अवधि के दौरान भारत को उस उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवधिक समीक्षा करेंगे, बशर्ते ये निर्यातक अथवा उत्पादक यह सिद्ध करते हैं कि वे निर्यातक देश के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से सम्बद्ध नहीं हैं, जिन पर उस उत्पाद हेतु पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है।
- (2) केन्द्रीय सरकार इस नियम के उप नियम (1) में यथा संदर्भित निर्यातकों अथवा उत्पादकों से किए गए आयातों पर जांच अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण नहीं करेगी।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार अनंतिम आकलन करे और यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी संस्तुति करते हों तो आयातक से गारंटी प्राप्त करे और यदि ऐसी समीक्षा की परिणति ऐसे उत्पादों अथवा निर्यातकों के संबंध में पाटन के निर्धारण में होती हो, तो ऐसे मामलों में वह समीक्षा की शुरुआत की तारीख से, भूतलक्षी प्रभाव से शुल्क अधिरोपित करेगी।"

13. विश्व व्यापार संगठन के करार के अनुच्छेद 9.5 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:-

"9.5 यदि कोई उत्पाद आयातक सदस्य में पाटनरोधी शुल्क के अधीन हो तो प्राधिकारी जाँच के अधीन निर्यातक देश में ऐसे किसी निर्यातक या उत्पादक के लिए पाटन के अलग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ तत्काल समीक्षा करेंगे जिसने जाँच अवधि के दौरान आयातक सदस्य को उत्पाद का निर्यात नहीं किया हो बशर्ते कि ये निर्यातक या उत्पादक यह दर्शा सकता हो कि वे निर्यातक देश में ऐसे किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित नहीं हैं जो उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अधीन हैं। ऐसी कोई समीक्षा आयातक सदस्य में सामान्य शुल्क निर्धारण और समीक्षा कार्यवाही की तुलना में सक्रिय आधार पर शुरू की जाएगी और चलाई जाएगी। समीक्षा के दौरान ऐसे निर्यातकों या उत्पादकों से आयातों पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाएगा। तथापि, प्राधिकारी मूल्यांकन को रोक सकते और/या यह सुनिश्चित करने के लिए गारंटी का अनुरोध कर सकते हैं कि यदि ऐसी समीक्षा के परिणामस्वरूप ऐसे उत्पादकों या निर्यातकों के संबंध में पाटन का निर्धारण होता है तो पाटनरोधी शुल्क को समीक्षा की शुरुआत की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से लगाया जा सके।"

14. उपर्युक्त नियम, विश्व व्यापार संगठन के करार के प्रावधानों और डी जी टी आर की विगत प्रथा के संबंध में, एक नई शिपर समीक्षा जांच संबद्ध देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क लगता है के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक के संबंध में अलग अलग पाटन मार्जिन का निर्धार करने के उद्देश्य से निम्नलिखित परिस्थितियों में की जानी है :

- i. यह कि निर्यातक अथवा उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है और

- ii. यह कि निर्यातक अथवा उत्पादक यह दर्शाते हैं कि वे निर्यातक देश जो संबंधित उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अधीन हैं, ने किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं हैं।

15. वर्तमान मामले में मैसर्स अजीज फाइबर्स लिमि. (उत्पादक/ निर्यातक) बांग्लादेश ने "पटसन उत्पाद" पटसन यार्न/ ट्वाइन (बहुपरत वाला/ केबल किया हुआ और एकल) और पटसन सेकिंग थैले" पर अलग अलग पाटन मार्जिन की मांग करते हुए प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया है और नई शिपर समीक्षा शुरू करने का अनुरोध किया है।
16. 'नई शिप्पर' के रूप में आवेदकों की पात्रता के संबंध में, प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा किये गये दावों का विस्तृत परीक्षण जिसमें उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े/ सूचना के संबंध में प्रस्तुत किये गये विभिन्न दस्तावेजों का तालिका अध्ययन शामिल है, किया है। इस प्रकार की जांचों को नियम 22 की अपेक्षाओं और प्राधिकारी की विगत प्रथाओं को देखते हुए आयोजित की गई थी। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अनुरोधों को छोड़कर किसी ठोस साक्ष्यों के रूप में एन एस आर के लिए उत्पादक/ निर्यातक द्वारा शर्त को पूरा न किये जाने का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि उत्पादक/ आवेदक वर्तमान मामले में नई शिपर समीक्षा प्राप्त करने के पात्र हैं।

च. आवेदक के लिए अलग अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण

- i. **आवेदक उत्पादक की जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद और गैर विचाराधीन उत्पाद की समग्र बिक्री**

17. उत्पादक/ निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद (यार्न और सेकिंग थैला) और गैर विचाराधीन उत्पाद (सेकिंग कपड़े) दोनोंका उत्पादन और बिक्री नीचे दिये गये अनुसार किया है :

विवरण	यूनिट	यार्न
उत्पादक	मी. टन	***
कुल बिक्री	मी. टन	***
घरेलू बिक्री	मी. टन	***
भारत को बिक्री	मी. टन	***
तृतीय देशों को बिक्री	मी. टन	***

गणनावार/विभिन्नतावार बिक्री का ब्यौरा नीचे दिये गये अनुसार है :

क्र. सं.	पी. सी. एन.	भारत			तीसरे देश			घरेलू		
		कीमत (मी. टन.)	मूल्य (बी.डी.टी.)	मूल्य बी.डी.टी./ मी. टन.	कीमत (मी. टन.)	मूल्य (बी.डी.टी.)	मूल्य बी.डी.टी./ मी. टन.	कीमत (मी. टन.)	मूल्य (बी.डी.टी.)	मूल्य बी.डी.टी./ मी. टन.
	सी. बी.									
1	8 एलबीएस	-	-	-	***	***	***	-	-	-

[illegible]

ii. सामान्य मूल्य

18.

- क. तालिका के अध्ययन के दौरान कंपनी ने प्रतिनिधियों ने जांच की अवधि के लिए कंपनी की प्रमुख कच्चे माल अर्थात् दैनिक आधार पर मानवीय रूप से तैयार किया गया पटसन खरीद पंजी, उत्पादन रिकार्डों अर्थात् बंगला देश जूट स्पिन्नर एसो. (बी जे एस ए) को प्रस्तुत मासिक उत्पादन रिपोर्ट, मूल्यवर्धित कर विवरणी प्रतियां, विक्री रिकार्ड, लेखा परीक्षित लेखाओं से संबंधित अपने दावे के समर्थन में व्यौरा दिया। प्रेक्टिस करने वाले सनदी लेखाकार प्रमाण पत्र दिनांक 15.07.2019 ने यह प्रमाणित किया कि जांच की अवधि के लिए कंपनी की लेखा परीक्षित लेखाओं और अन्य लेखाओं/ वित्तीय रिकार्डों को रखा जा रहा है और उसकी सूचना बी एफ आर एस का पालन करते हुए आई सी ए बी द्वारा संदर्भित आई ए एस के अनुसार बंगला देश में आम तौर पर स्वीकार किये गये लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार दी गई है। उत्पादकों/ निर्यातकों का मूल रिकार्ड कुल मिलाकर पेशेवर तरीके से व्यवस्थित नहीं रखा गया था और वह बंगला में भी था और उसका अनुवाद आवश्यक था। हालांकि जांच की अवधि की लेखा परीक्षित लेखाओं पर उत्पाद की लागत की गणना करने के लिए आधार के रूप में विचार किया गया है। कंपनी ने यार्न, सेकिंग कपड़े और सेकिंग थैले के लिए अलग अलग लेखांकन/ लागत रिकार्ड अनुरक्षित नहीं किया है। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार/ काउंट के यार्न (अर्थात् सी बी, सी आर टी, सी आर टी और विभिन्न एल बी एस और काउंट के आशोधित वनस्पति तेल) सेकिंग कपड़े और सेकिंग थैले (विभिन्न एल बी एस और काउंट के) का उत्पादन कंपनी द्वारा किया जा रहा है और विभिन्न प्रकार के यार्नों और सेकिंग थैलों के बीच विक्री कीमतों में अंतर है।
- ख. जांच की अवधि के दौरान कंपनी ने *** मी. ट. यार्न, *** मी. ट. सेकिंग कपड़े और *** मी. ट. सेकिंग थैले का उत्पादन किया है, क्योंकि कंपनी उत्पादन कर रही है, किसी आवंटन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, पी. ओ. आई. के लिए लेखा परीक्षित लेखों पर आधारित बैंक प्रभारों पर विचार करने के पश्चात यार्न के उत्पादन की औसत लागत को बी. डी. टी. ***/ मी. टन तैयार किया गया है।
- ग. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मूल जांच में, यार्न के "सामान्य मूल्य" की गणना करने के लिए अपनी गई पद्धति यार्न की सभी किस्मों सहित भारत औसत आधार पर थी। मूल जांच ऐतिहासिक जांच की अवधि के आधार पर की गई थी और अनुकूल पाटन मार्जिन के लिए समायोजित की जा रही निर्यात कीमत के लिए अवसर उपलब्ध नहीं था जैसा कि नई शिपर समीक्षा में हो सकता था। इस कारण से भारत औसत दृष्टिकोण व्यापक तौर पर सांकेतिक होंगे। नई शिपर की समीक्षा होने के कारण वर्तमान मामला जिसमें भारत में निर्यात किये गये यार्न किस्मों की अलग अलग और कीमत है। उत्पादन का ग्रेडवार/ काउंट वार लागत एक महत्वपूर्ण मानदंड है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह देखते हुए कि यार्न की विभिन्न किस्मों के लिए कोई काउंट वार लागत उपलब्ध नहीं कराई गई है, यह संभव नहीं है कि विचाराधीन उत्पादन अर्थात् काउंट वार/ किस्म वार के आधार पर यार्न की लागत की गणना की जाये और जैसी भी स्थिति हो घरेलू अथवा उपयुक्त रूप से तीसरे देश के निर्यातों के लिए ओ सी टी जांच की जाये। इन व्यवस्थाओं के कारण प्राधिकारी जांच की अवधि के दौरान भारत में निर्यात किये गये विभिन्न किस्म के यार्न के लिए सामान्य मूल्य स्थापित करने में असमर्थ हैं। प्राधिकारी ने आवेदक उत्पादक/ निर्यातक द्वारा की गई टिप्पणियों और बांग्लादेश उच्चायोग तथा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदनों पर उचित रूप से अंतिम पैरों में प्रकटन विवरण के उत्तर में विचार किया है।

iii. निर्यात कीमत

19. प्राधिकारी दोहराते हैं कि 30 अगस्त, 2019 के प्रकटन विवरण में यह धारित किया गया था कि उत्पादक/ निर्यातक ने भारत को सीधे ही निर्यात किया था। पी. ओ. आई. के दौरान उन्होंने (ई आर *** बी डी टी/ डालर) (सी. एन. एफ.) के बीजक मूल्य पर *** मी. ट. की कुल 16 खेपों का निर्यात किया है। क्रमशः ***, *** और *** डॉलर/ मी. टन का इन समायोजन का दावा अंतर्देशीय भाड़े पोर्ट पर खर्च और बैंक शुल्कों पर हुए वास्तविक खर्च के आधार पर किया गा है। उपर्युक्त के आधार पर भारत में औसत निवल निर्यात कीमत का दावा *** अमरीकी डॉलर मी. टन है।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादक/ निर्यातक ने भारत को पी. ओ. आई. के दौरान *** मी. ट. यार्न का निर्यात किया है जिसमें हैसियन और सेकिंग किस्म हैं। पी. ओ. आई. में क्रमशः आवेदक निर्यातक द्वारा यार्न निर्यात बंगलादेश से कुल आयातों का क्रमशः 1-2 प्रतिशत है।

प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच करने के लिए बंगला देश से अन्य निर्यातकों के साथ आवेदक द्वारा भारत में जांच की अवधि के दौरान संभव सीमा तक नमूना आधार पर यार्न की विभिन्न किस्मों के निर्यात की कीमतों की तुलना की है कि क्या आवेदक निर्यातक के यार्न की विभिन्न किस्मों की निर्यात कीमतें वास्तविक थीं। दो विशिष्ट प्रकारों अर्थात् ग्रेड 14/1 और 28/1 के आवेदक निर्यातक की सेकिंग किस्मों की निर्यात कीमत की तुलना अन्य निर्यातकों (आवेदक के कुल निर्यात का 6 प्रतिशत है) करने पर यह नोट किया जाता है कि आवेदक निर्यातक की निर्यात कीमतें इन दो विशिष्ट श्रेणियों (औसत आधार पर 15-20 प्रतिशत) है। अन्य विशिष्ट श्रेणियों के लिए इस प्रकार की तुलना के लिए तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, जैसा कि ऊपर में उल्लेख किया गया है दो श्रेणियों की तुलना करने पर प्राधिकारी इसे उपयुक्त नहीं मानते हैं कि आवेदक निर्यातक की निर्यात कीमत को विश्वसनीय माना जाये। निर्यात कीमत पर विचार किए जाने पर आवेदक उत्पादक/ निर्यातक और घरेलू उद्योग के प्रकटन पश्चात निवेदनों पर बाद के पैरों में उचित रूप से विचार किया गया है।

iv. पाटन मार्जिन

20. प्राधिकारी उपर्युक्त (iii) और (ii) को देखते हुए इस जांच के अधीन विचाराधीन उत्पाद के लिए अलग अलग पाटन मार्जिन स्थापित करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि, प्राधिकारी ये नोट करते हैं कि आवेदक उत्पादक ने समग्र आधार पर उत्पादन की लागत उपलब्ध कराई है। यदि भारत में निर्यात किये गये यार्न की सभी किस्मों के लिए उत्पादन की भारित औसत लागत 5 प्रतिशत के उपयुक्त लाभ के साथ और (उपर्युक्त (iii) में उल्लिखित कीमत अंतर को देखते हुए उपयुक्त रूप से समायोजित) की निर्यात कीमत की तुलना की जाये तब मूल जांच में नमूने न लिये गये उत्पादकों/ निर्यातकों पर लागू की गई शुल्क की सीमा में पाटन स्पष्ट होगा। भारत में सेकिंग थैले की निर्यात मात्रा विश्वसनीय निर्यात कीमत स्थापित करने के लिए बहुत नगण्य है। प्राधिकारी अंतिम निर्धारण में इन पहलुओं पर उपयुक्त रूप से विचार करने का प्रस्ताव करते हैं।

छ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

21. घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले मै० टी. पी. एम. ने निम्नलिखित प्रकटन पश्चात टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं :-

- एन. एस. आर. जांच में यह दर्शाने की जरूरत है कि नई शिपर समीक्षा मामले में जांच की अवधि के दौरान नए शिपर आवेदक द्वारा किए गए निर्यात विश्वसनीय व्यावसायिक लेनदेन हैं जिन्हें पाटन मार्जिन के लिए आधार बनाए जाने की जरूरत है। इसका प्रयोजन "व्यापार के उचित मूल्य को सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि इसकी व्यापारिक तर्कसंगतता के लिए प्रत्येक बिक्री की जांच करना" है।

- ii. आयात मात्रा कुल आयातों का नगण्य है। इसके अतिरिक्त, निर्यातक को निर्यात मात्रा के संबंध में निर्यात कीमत की उपयुक्तता और विश्वसनीयता स्थापित करनी चाहिए। प्राधिकारी द्वारा की गई जांच दर्शाती है कि निर्यात कीमत प्रतिनिधि नहीं है।
- iii. यह दर्शाने के लिए निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराया गया कोई कारण वास्तविक अन्यथा नहीं है कि कैसे निर्यातक ने अन्यो की तुलना में अन्य कीमत पर वस्तुओं का निर्यात करने में सक्षम हैं, क्योंकि समान प्रकार की वस्तुएं काफी कम कीमत पर आयातित की जा रही हैं।
- iv. अन्य पैरामीटर जिनकी निर्यात कीमत की उपयुक्तता के लिए जांच की जा सकती है जैसे कीमत आय पर घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की है। जब तक कि निर्यातकों ने विभिन्न पक्षकारों के लिए कीमतों में विभिन्नताओं, आयातक और इसके क्रयकर्ता तथा निर्यातक और आयातक के बीच क्षतिपूरक प्रबंधों की अनुपस्थिति, कीमत जिस पर आयातक द्वारा बिक्री माल की फर्न बिक्री की गई है, आदि।
- v. आवेदकों ने भारत में आयातक से प्रश्नावली उत्तर की मांग करने का कोई प्रयास नहीं किया है। भारत में आयातक इस जांच में सामने नहीं आए हैं। आयातकों से किसी प्रश्नावली उत्तर न प्राप्त होने को ध्यान में रखते हुए, आवेदक ने स्थापित नहीं किया है कि कैसे निर्दिष्ट प्राधिकारी आयात कीमत की उपयुक्तता को सुनिश्चित कर सकते हैं।
- vi. आवेदकों ने ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया है जिसे यह अर्थ निकाला जा सके कि आवेदकों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह दर्शाया है कि वे नियम 22 के तहत अनिवार्यता को पूरा करते हैं।

22. **मै० एम. एस. पोथल और एसोसिएट्स जो निर्यातक/ उत्पादक का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित प्रकटन पश्चात टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं :-**

क. आवेदक द्वारा उत्पादित पी. यू. सी. के सामान्य मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में लागत की अस्वीकृति के आधार पर पुनर्विचार की जरूरत है, क्योंकि अस्वीकृति न्यायोचित और निष्पक्ष नहीं है।

- i. किसी उत्पादक या निर्यातक द्वारा निर्यातित किसी वस्तु के लिए पाटन मार्जिन के निर्धारण का कानूनी ढांचा धारा 9क (6क) के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है। और प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए अनुबंध-1 को लागू करते हुए नियम 10 के तहत नियमों को तैयार किया गया है।

“सामान्य मूल्य निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन को निर्धारित करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य के साथ साथ निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे:-

1. सामान्य मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में संदर्भित लागतों के मूल तत्व सामान्य रूप से जांचाधीन निर्यातक अथवा उत्पादक द्वारा रखे गए रिकार्डों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे बशर्ते कि ऐसे रिकार्ड निर्यातक देश के सामान्यता स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में हों और ऐसे रिकार्ड उचित रूप से विचाराधीन वस्तु के उत्पादन और बिक्री की संबद्ध लागत को प्रतिबिंबित करते हों। ”
(दबाव वर्धित)

- ii. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 की उक्त विषय वस्तु का आधार डब्ल्यू. टी. ओ. के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 में है। अनुच्छेद 2.2.1.1 की अनिवार्यताओं की व्याख्या करते समय, इजिप्ट - स्टील रेबार में डब्ल्यू. टी. ओ. पैनल ने नोट किया है कि अनुच्छेद 2.2.1.1 और 2.2.2 दोनों, दो संघटकों पर जोर देते हैं, प्रथम उत्पादन की लागत को वास्तविक बहियों और प्रश्नाधीन कंपनी द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों के आधार पर

- परिकलित किया जाना चाहिए। अब तक चूंकि ये सामान्य रूप में स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के साथ रखे जाते हैं किंतु द्वितीय, शामिल की जाने वाली लागतें वह हैं जो उचित रूप से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के साथ संबद्ध लागतों को उचित रूप से दर्शाती हैं।
- iii. वर्तमान जांच में, आवेदक ने कंपनी के द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों के अनुसार विचाराधीन उत्पाद से संबंधित लागत सूचना प्रस्तुत की है जो जी. ए. ए. पी. के अनुसार है। कंपनी के पास यार्न की विभिन्न विविधताओं के लिए गणनावार लागत अनुरक्षित करने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यह लागत निर्धारण कारोबार के सामान्य कार्य का हिस्सा नहीं है। प्रकटन का पैरा 17. ख. स्वीकार करता है कि आवेदक पी. यू. सी., जो कि पटसन यार्न है, के एकल प्रकार का एक उत्पादक है और उसकी लागत उपलब्ध थी। प्रकटन विवरण में पैरा 17. ग., जैसाकि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है कहीं नहीं कहता है कि आवेदक यह दर्शाने में असफल रहा है कि उनके लागत रिकार्ड जी. ए. ए. पी. के अनुरक्षित किए गए हैं अथवा लागतों का कोई अवयव लागत के किसी विशिष्ट अवयव की शर्तों में पी. यू. सी., जोकि यार्न (पटसन उत्पाद) है, के साथ संबद्ध लागत को नहीं दर्शाता। इसके अतिरिक्त, कृपया नोट करें कि कंपनी तीन प्रकार के यार्न उत्पादित करती है अर्थात् सी. बी., हैसियन और सेकिंग, इन तीन विविधताओं के भीतर, तीनों विविधताओं में प्रत्येक में बहुत सी गणना हैं और गणना में बहुत बड़ी संख्या में प्लाइज हैं, अतः किसी छोटे स्तर की कंपनी के लिए पी. सी. एन. में प्रत्येक के लिए प्रकारवार कच्ची सामग्री की लागत को बनाए रखना व्यवहार्य नहीं होगा। यह अवलोकन किया गया है कि गणनावार/ विविधतावार पर विभिन्न प्रकारों के यार्न के उत्पादन की लागत को परिकलित करना संभव नहीं है, क्योंकि गणनावार लागत निर्धारण उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह संबंधित पी. यू. सी. की अस्वीकृति के लिए एक उचित आधार नहीं हो सकता।
- iv. चूंकि आवेदक ने पी. यू. सी., जोकि यहां यार्न है, के लिए लागत उपलब्ध कराई है, यह अवलोकन कि पी. यू. सी. के लिए संगत लागत उपलब्ध नहीं हैं, पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। हालांकि, बाद में प्रकटन भाग में प्राधिकारी ने नोट किया कि आवेदक ने पी. यू. सी. के लिए भारांशित औसत लागत उपलब्ध कराई है। जहां तक विभिन्न प्रकार के यार्न का संबंध है, आवेदक ने सुझाव दिया है कि कच्ची सामग्री और कच्ची सामग्री की लागत के कारण मुख्य लागत को यार्न के विभिन्न प्रकारों के संबंध में बिक्री मूल्य अनुपात पर आवंटित किया गया है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई उत्पाद जिसकी बाजार में अधिक आय है, की लागत भी उच्च होगी। यह पद्धति सही है और यह प्राधिकारी को यार्न की प्रकारवार लागत निर्धारित करने में सक्षम बना सकता है। हालांकि, नियम की आवश्यकता पी. यू. सी. के लिए लागत निर्धारित करने के लिए है न कि इसके विभिन्न प्रकारों के लिए पक्षपात के बिना, उपर्युक्त आधार पर यार्न की प्रकारवार लागत संलग्न है।
- v. प्रकारवार लागत के संदर्भ में आवेदक ने यह भी प्रस्तुत किया है कि डब्ल्यू. टी. ओ. ए. डी. करार का अनुबंध-11 स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति के बारे में बताता है जहां उपलब्ध कराई गई सूचना अनुबंध-11 के पैरा 5 पर सभी प्रकार में आदर्श नहीं होगी। इस संदर्भ में प्रकारवार लागत की अनुपस्थिति पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। करार स्पष्ट रूप से कहता है कि हालांकि, उपलब्ध कराई गई सूचना सभी पहलुओं में आदर्श नहीं हो सकती है, यह प्राधिकारियों द्वारा इसकी उपेक्षा करने को न्यायोचित नहीं ठहराता। वर्तमान मामले में, आवेदक ने उसकी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार काम किया है, क्योंकि आवेदक ने पी. यू. सी. स्तर पर अपने रिकार्डों के अनुसार लागत उपलब्ध कराई है और उचित आवंटन आधार पर प्रकारवार लागत भी उपलब्ध कराई है। प्रकारवार आधार पर लागत का निर्धारण आवंटन का मामला हो सकता था और इसके लिए एक व्यावहारिक और सामान्य तौर पर अनुसरित पद्धति का भी सुझाव दिया गया था।

- vi. उपर्युक्त के होते हुए भी विवादास्पद प्रश्न जो पैरा 1.7 में प्राधिकारी के अवलोकन से उभरता है कि क्या प्राधिकारी इस मुख्य कारण के लिए नई शिपर समीक्षा में सामान्य मूल्य के संदर्भ में जांचाधीन वस्तु की लागत के निर्धारण में एक भिन्न दृष्टिकोण अपना सकता है कि वर्तमान एन. एस. आर. की पी. ओ. आई. एक भविष्य सापेक्ष अवधि है जो निर्यातों के समय आवेदक को ज्ञात, होती है अथवा विचाराधीन जांच एक नई शिपर समीक्षा है ? हमारा आदरपूर्ण निवेदन है कि ऐसे दृष्टिकोण का कोई कानूनी आधार नहीं है और अनुबंध-1 में उपलब्ध कराई गई पद्धतियां पाटन मार्जिन के प्रत्येक निर्धारण में लागू होती हैं चाहे वह नई जांच हो अथवा नई शिपर समीक्षा हो। इसके अतिरिक्त, जांच का स्वरूप स्वभावतः जोकि यहां एन. एस. आर. है, किसी भी प्रकार से लागत के औचित्य पर न तो प्रतिकूल प्रभाव डालता है उसे या निष्प्रभाव करता है न ही जांच का स्वरूप लागत की युक्तिसंगतता को विवादास्पद बनाने का आधार हो सकता है और लागत की युक्तिसंगतता की आवेदक के दावों में सन्निहित लागत के विभिन्न अवयवों की युक्तिसंगतता के आधार पर जांच की जानी चाहिए और केवल जांच के स्वरूप का उल्लेख करते हुए अनुमानित आधार पर नहीं की जानी चाहिए। आदरपूर्वक यह निवेदन किया जाता है कि ऐसा दृष्टिकोण नई शिपर समीक्षा के प्रयोजन के विरुद्ध जाता है, जैसाकि ए. डी. करार के अनुच्छेद 9.5 में परिकल्पित किया गया है और ऐसा दृष्टिकोण आवेदक के अधिकारों को गंभीर रूप से क्षति पहुंचा सकता है। आदरपूर्वक निवेदन किया जाता है कि ऐसा दृष्टिकोण नई शिपर समीक्षा के उद्देश्य के विरुद्ध जाता है जो ए. डी. करार के अनुच्छेद 9.5 में परिकल्पित किया गया है और ऐसा दृष्टिकोण गंभीर रूप से आवेदक को अधिकारों को क्षति पहुंचा सकता है और वर्तमान मामले में भावी पी. ओ. आई. की प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया जैसाकि कानून के तहत अनुमेय है। एक बार विधि के तहत यथा अनुमेय पी. ओ. आई. के निर्धारित हो जाने के पश्चात, इसे आवेदक द्वारा दावा की गई कीमत और लागत की विश्वसनीयता पर शंका करने का आधार नहीं माना जा सकता और ऐसी धारणाएं वर्तमान जांच के आधार के विरुद्ध जाती हैं। अनुरोध किया जाता है कि सामान्य मूल्य को कृपया नियमावली के अनुबंध-1 में परिकल्पित सिद्धांतों के आधार पर परिकल्पित किया जाना चाहिए अर्थात् किसी भी ए. डी. जांच के समान सामान्य मूल्य के संदर्भ में लागत का निर्धारण और इसकी लागत को निर्धारित करते समय एन. एस. आर. आवेदक को पृथक आधार पर नहीं रखा जाना चाहिए।
- vii. यह भी निवेदन किया जाता है कि कानून की अनिवार्यता विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रकारवार नहीं पाटन मार्जिन निर्धारित करना है और एवं इस संदर्भ में पी. यू. सी. की लागत की अवहेलना करते हुए, जो जी. ए. ए. पी. के आधार पर कंपनी द्वारा अनुरक्षित किए गए रिकार्डों के अनुसार, बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। ई. सी. - बेड लिनेन में, डब्ल्यू. टी. ओ. अपीलीय निकाय ने निम्नानुसार पाया है :-

"53 हम पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4.2 या किसी अन्य प्रावधान में ऐसा कुछ नहीं पाते हैं जो विचाराधीन उत्पाद के प्रकारों या मॉडल्स के लिए पाटन के 'मार्जिन की विद्यमानता' की स्थापना के लिए उपलब्ध कराया गया हो, इसके विपरीत 'पाटन के मार्जिन की विद्यमानता' की स्थापना से संबंधित सभी संदर्भ उस उत्पाद से संदर्भित हैं जो जांच के विषय हैं। इसी प्रकार, हम किसी पाटन रोधी जांच में, उस धारणा का समर्थन करने के लिए अनुच्छेद 2.4.2 में कुछ नहीं पाते । पाटनरोधी करारों के इस प्रावधान द्वारा दो विभिन्न स्तरों की परिकल्पना की है या प्रतिष्ठित किए गए हैं न ही यूरोपीय समितियों के न्यायोचित सिद्ध करने के लिए इन दो 'स्तरों' के आधार पर समान उत्पाद के प्रकारों या मॉडल्स के बीच प्रभेद बनाया जा सकता है। हमारे विचार में पाटन मार्जिन का परिकलन करने के लिए चाहे जिस पद्धति का प्रयोग किया जाए, इन मार्जिनों को अनिवार्यतः और केवल इन्हें ही समग्र के रूप में जांचाधीन उत्पाद के लिए स्थापित किया जा सकता है। हम यूरोपीय समुदायों के साथ सहमत नहीं हैं कि अनुच्छेद 2.4.2 इस संबंध में कोई मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं कराता कि कैसे विचाराधीन उत्पाद के लिए समग्र पाटन मार्जिन को परिकलित किया जाए" (दबाव वर्धित) ।

- viii. इस प्रकार, पी. यू. सी. के परस्पर प्रकारों की आवेदक द्वारा अनुरक्षित प्रकारवार/ गणनावार अनुपस्थिति आवेदक द्वारा अनुरक्षित पी. यू. सी. की लागत को अस्वीकृत करने का आधार नहीं हो सकता। यदि आवेदक दो प्रमुख जरूरतों के अनुसार पी. यू. सी. की लागत प्रस्तुत करने में असफल रहता अर्थात् जी. ए. ए. पी. अनुसार रिकार्ड और नियम में उपलब्ध कराए गए अनुसार लागत की उपयुक्तता, तो यह पृथक् मुद्दा होता। वर्तमान मामले में, आवेदक ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियम के अनुसार अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और उसमें दिए गए आधारों के लिए लागत की अस्वीकृति बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है और हम न्याय और निष्पक्षता के हित में इस प्रकार दुबारा विचार करने के लिए प्राधिकारी के समक्ष निवेदन करते हैं।

ख. निर्यात कीमत की अस्वीकृति के लिए आधार, जैसाकि दावा किया गया है, आवेदक के बारे में पुनर्विचार की आवश्यकता है, क्योंकि अस्वीकृति न्यायपूर्ण और निष्पक्ष नहीं है।

- i. प्राथमिक निवेदन के रूप में, यह दोहराया जाता है कि आवेदक ने संबद्ध वस्तुओं की उल्लेखनीय मात्रा निर्यातित की है और अभिभावी बाजार कीमत की अपेक्षा अनुचित रूप से ऊंची कीमत पर ऐसी मात्रा स्तर पर बिक्री संभव नहीं है। आवेदक ने अभिभावी बाजार कीमतों से तुलनीय कीमतों पर निर्यात किया है और यह किसी भी प्रकार से बढ़ा हुआ मूल्य नहीं है।
- ii. आवेदक की निर्यात कीमत की तुलना नमूने के रूप में अन्य निर्यातकों द्वारा किए गए कुछ निर्यातों के साथ करना आवेदक की निर्यात कीमत की विश्वसनीयता को जांचने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि चुना गया नमूना व्यापार की मात्रा और स्तर के रूप में किसी भी प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं करता। आवेदक ने दिनांक 1.9.2019 के अपने पत्र के अनुसार उचित तुलना के लिए बांग्लादेश से पी. यू. सी. के निर्यातों के संपूर्ण आंकड़ों के लिए अनुरोध किया था, किंतु इसे उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसी कोई भी तुलना युक्तिसंगत आधार पर होनी चाहिए और यहां चुने गए नमूने अमहत्वपूर्ण हैं। जब तक, आवेदक की निर्यात कीमत की अन्य निर्यातकों द्वारा पी. ओ. आई. के दौरान भारत को बांग्लादेश से पी. यू. सी. के समान प्रकार के कुल निर्यात के महत्वपूर्ण भाग से तुलना नहीं की जाती, इस दृष्टिकोण में किसी विरूपण के बिना उचित परिणाम पर नहीं पहुंचा जा सकता।
- iii. परिपुष्ट नमूने में प्राधिकारी द्वारा जिस निर्यात कीमत पर भरोसा किया गया है, वह निर्यात कीमत सी. आई. एफ. स्तर पर लिया गया प्रतीत होता है न कि पहुंच स्तर पर। अधिकतर निर्यातकों के लिए पी. यू. सी. पर ए. डी. डी. लगाया गया है और किसी भी कीमत की तुलना में ऐसे शुल्क को ध्यान में रखना अनिवार्य है। आवेदक ने वर्तमान समीक्षा के अधीन पी. यू. सी. का निर्यात किया और आयातों के समय ऐसे पी. यू. सी. पर कोई ए. डी. डी. प्रयोज्य नहीं था। इस प्रकार, से निर्यातक की अवशिष्ट श्रेणी में किसी निर्यातक से आयात करने वाले किसी आयातक की आयात कीमत, जिस पर निम्नतम शुल्क लगता है और ऐसे निर्यातक जिस पर कोई शुल्क नहीं लगता, की समान स्तर पर तुलना नहीं की जा सकती है। शुल्क का अवयव स्पष्ट रूप से आयातक की ओर से कीमत में आता है और यह देखने के लिए कोई भी तुलना पहुंच कीमत पर की जानी चाहिए कि आयातों की वास्तविक कीमत क्या थी। इस प्रकार, यह अवलोकन कि आवेदक की कीमत 15-20 प्रतिशत उच्च थी और इसलिए विश्वसनीय नहीं है, की व्यापार के तथ्यों के आधार पर पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है।
- iv. यहां यह नोट किया जाना चाहिए कि आवेदक ने पी. ओ. आई. पश्चात की अवधि में भारत को संबद्ध वस्तुओं का भी आयात किया था। पी. ओ. आई. पश्चात आयात पाटन मार्जिन के निर्धारण पर कोई बोज़ नहीं डालते और पी. ओ. आई. पश्चात की कीमतों कीमतों के ऐसे स्तर को प्रदर्शित करती है जो पी. ओ. आई. की कीमतों से तुलनीय हैं। कृपया यहां यह नोट किया जाना चाहिए कि कंपनी ने पी. ओ. आई. पश्च अवधि में उल्लेखनीय मात्रा निर्यात की है जो कीमत की विश्वसनीयता और सामंजस्य को दर्शाता है। हम प्राधिकारी से पी. ओ.

आई. के लिए आवेदक द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत की सच्चाई की जांच करने के लिए भी निर्यात की पी. ओ. आई. पश्च कीमत पर विचार करने का अनुरोध करते हैं। पी. ओ. आई. पश्चात अवधि के दौरान की कीमत स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि निम्न मार्जिन को प्राप्त करने के लिए कीमत को बढ़ाने का निर्यातक का आरोप निराधार है।

- v. इसके अलावा, हम बांग्लादेश जूट मिल्स कारपोरेशन द्वारा जारी एक परिपत्र संलग्न कर रहे हैं, जिसमें यह देखा जा सकता है कि सी. बी. 10 एल. बी. एस./ 1 प्लाई के लिए कीमत को अंतर्राष्ट्रीय निर्यात कीमत के रूप में *** अमरीकी डॉलर प्रति मी. टन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। पी. ओ. आई. के दौरान हमारी कीमत *** बी डी टी थी जो *** अमरीकी डॉलर प्रति मी. टन के समकक्ष है। यह देखा जा सकता है कि हमारी कीमत सरकार द्वारा निर्णीत कीमत से तुलनीय है। इस परिपत्र की प्रासंगिकता यह है कि हांलाकि ऐसी कीमतें बेंचमार्क के रूप में दृढ़ता से बाध्यकारी नहीं हैं, ऐसी कीमतें स्पष्ट रूप से बाजार में अभिभावी कीमत रेंज को दर्शाती है और आवेदक ने भारत को ऐसी अधिसूचित कीमत के तुलनीय एक वास्तविक कीमत पर भी निर्यात किया। यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने ऐसी अवास्तविक कीमत पर निर्यात किया जो उस कीमत के समकक्ष नहीं है जिस पर अन्य निर्यातक विचार कर रहे थे।
 - vi. हम बांग्लादेश जूट गुड्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन द्वारा जारी एक पत्र भी संलग्न कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 14/1 और 28/1 सेकिंग क्वालिटी यार्न की अंतर्राष्ट्रीय कीमत का प्रकटन किया है, यह कीमत पी. ओ. आई. के दौरान हमारी निर्यात कीमत से भी मेल खाती है। यह इस तथ्य की ओर भी संकेत करता है कि आवेदक भारत को किसी नकली कीमत पर निर्यात नहीं कर रहा था और ऐसी कीमतें बाजार बोलचाल में अत्यधिक अभिभावी थी।
 - vii. अतः, उपर्युक्त के आधार पर, निवेदन किया जाता है कि प्रकटन में प्रस्तावित किए गए अनुसार, आवेदक द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत पर प्राधिकारी के दृष्टिकोण पर तथ्यों के आधार पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है और हम न्याय और उपयुक्तता के हित में इसका समर्थन करते हैं।
- ग. आवेदक भारत को उसके निर्यातों के मामले में पृथक पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्रमाणनीय सूचना उपलब्ध करा सकते थे। एक वैकल्पिक पद्धति के लिए किसी प्रस्ताव का इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए।**
- i. नई शिपर समीक्षा को अभिशासित करने वाले पाटनरोधी नियमों का नियम 22 स्पष्ट रूप से बताता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को किसी निर्यातक या उत्पादकों के लिए पाटन के पृथक-पृथक मार्जिनों का निर्धारण करने के प्रयोजनाएं एक आवधिक समीक्षा आयोजित करेगा। आवश्यकता स्पष्ट रूप से पृथक पाटन मार्जिन के निर्धारण की है और यह विगत में या कुछ अन्य पक्षकारों के लिए निर्धारित कुछ अन्य मार्जिनों का रूपांतरण नहीं हो सकता।
 - ii. आदरपूर्वक यह भी निवेदन किया जाता है कि समान पी. यू. सी. के संबंध में जनता जूट मिल एन. एस. आर. के संबंध में एक हाल ही की एन सी आर में प्राधिकारी ने नान-सैपल श्रेणी के लिए मार्जिनों पर आधारित अलग-अलग मार्जिन निर्धारित किया है। तथापि, प्राधिकारी ने मेलामाइन के संबंध में एक अंतिम जांच के विषय पर उक्त निर्धारण पर अपनी स्थिति इस प्रकार स्पष्ट की है ; "प्राधिकारी नोट करते हैं कि समान निर्धारण में प्राधिकारी ने निर्यात कीमत के औचित्य और विश्वसनीयता को स्थापित करने की जरूरत पर जोर दिया है और मामले के तथ्यों द्वारा बाधित हो कर आवेदक को ए डी शुल्क की केवल नान-सैपल श्रेणी प्रदान करने का निर्णय किया है।
 - iii. अतः, जनता जूट मिल मामले में गैर-नमूना श्रेणी के लिए मार्जिन को अपनाना उक्त मामले में कुछ विशेष तथ्यात्मक बाध्यताओं के परिणाम या और वर्तमान मामले में ऐसी कोई बाधा नहीं है। आवेदक ने व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए विवरण उपलब्ध कराए हैं और पी. ओ. आई. के दौरान आवेदक द्वारा किए गए

- निर्यात महत्वपूर्ण थे। कुछ अन्य मामलों में कुछ बाध्यकारी परिदृश्यों के तहत अपनाए गए किसी दृष्टिकोण को नियम नहीं माना जा सकता। विशेष रूप से नियम 22 में दी गई स्पष्ट कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जो प्राधिकारी के लिए उनके संगत आंकड़े के आधार पर नई शिपर्स के लिए पृथक मार्जिन निर्धारित करना अनिवार्य बनाता है। न तो नियमों में और न ही पाटनरोधी करार में ऐसे किसी प्रावधान की व्यवस्था की गई है जो प्राधिकारी को इसके जैसे मूल मामले में निर्यातकों की गैर-नमूना श्रेणी के मार्जिन जैसे स्वयं के डाटा आधारित पृथक मार्जिन के अलावा एन एस आर आवेदक के लिए मार्जिन अपनाने में सक्षम बनाता है।
- iv. पक्षपात के बिना, यह हमारा आदरपूर्ण निवेदन है कि प्राधिकारी को आवेदक के लिए पृथक मार्जिन निर्धारित करने की स्थिति में होना चाहिए और इन टिप्पणियों पर उचित विचार करने के पश्चात उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना को अपनाने अथवा किसी अन्य आधार को अपनाने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.8 के प्रति प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे जो जांच अधिकारियों को केवल ऐसे मामलों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण करने की अनुमति देता है जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनिवार्य सूचना तक पहुंच प्रदान करने से इंकार करता है अथवा अन्यथा रूप से सूचना उपलब्ध नहीं कराता अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से हस्तक्षेप करता है। उपर्युक्त स्थितियों में से कोई भी एन एस आर आवेदक पर लागू नहीं होती क्योंकि आवेदक ने प्राधिकारी से पूरी तरह से सहयोग किया है। और प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किसी भी अन्य सूचना को भी उपलब्ध कराने में इच्छुक थे ;
- क. अर्जेटीना – सिरेमिक टाइल्स में, पैनल ने धारित किया है कि “यह हमें स्पष्ट है और दोनों पक्षकार सहमत हैं कि कोई जांच प्राधिकारी प्राथमिक स्रोत सूचना की अनदेखी कर सकता है और केवल ए डी करार के अनुच्छेद 6.8 और अनुबंध-II की विशिष्ट स्थितियों के तहत उपलब्ध तथ्यों का आश्रय ले सकता है। इस प्रकार, कोई जांच अधिकारी केवल उपलब्ध तथ्यों का आश्रय ले सकता है जहां कोई पक्षकार: (i) अनिवार्य सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है; (ii) अन्यथा रूप से किसी उचित अवधि के भीतर अनिवार्य सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहता है; (iii) जांच में उल्लेखनीय रूप से हस्तक्षेप करता है।
- ख. यू. एस. – स्टील प्लेट मामले में, पैनल ने परिसीमा का विश्लेषण किया जो अनुबंध-II के पैराग्राफ 3 प्रस्तुत की गई सूचना का अस्वीकृत करने इसके स्थान पर और उपलब्ध तथ्यों का आश्रय लेने के लिए जांचकर्ता प्राधिकारियों को अधिकार प्रदान करता है और संयुक्त राष्ट्र की स्थिति को स्वीकार नहीं करता कि अनुच्छेद 6.8 में ‘सूचना’ से तात्पर्य संपूर्ण सूचना से है, ऐसे सदस्यों के पास किसी मामले में प्रस्तुत सभी सूचनाओं को अस्वीकार करने का असीमित अधिकार प्राप्त होता है जहां कोई अनिवार्य सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है।
- ग. यू. एस. – हॉट रोलड स्टील और यू. एस. स्टीक प्लेट से समर्थन प्राप्त ई सी- साल्मैन (नार्वे) में पैनल धारित करता है कि “अनुबंध-II का पैराग्राफ 3 जांच प्राधिकारियों को इसके निर्धारणों के प्रयोजनार्थ सभी प्रस्तुत की गई सूचनाओं को ध्यान में रखने का निर्देश देता है जब वे (i) सत्यापनीय (ii) उचित रूप से प्रस्तुत की गई हो ताकि इनका अनुचित कठिनाइयों के बिना जांच में प्रयोग किया जा सके; (iii) एक समय पर आपूर्ति की गई और, जहां, प्रयोज्य था ; (iv) प्राधिकारियों द्वारा अनुरोधित माध्यम या कंप्यूटर भाषा में आपूर्ति की गई। इस प्रकार, अनुबंध-II का पैराग्राफ 3 जांच प्राधिकारियों को ऐसी सारी सूचना को ध्यान में रखने की मांग करता है जो निर्धारणों को निश्चित करते समय तीन अथवा कभी-कभी चार संचयी स्थितियों को पूरा करते हैं। यह अनुसारित करता है कि जहां सभी स्थितियों को पूरा किया गया है, किसी जांच प्राधिकारी निर्धारण करते समय प्रस्तुत की गई सूचना को अस्वीकृत करने के हकदार नहीं होंगे।

23. बांग्लादेश उच्चायोग द्वारा दायर प्रकटन के संबंध में टिप्पणियां

- i. संबंधित तीनों कंपनियों ने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली उत्तर फॉर्मेट में और समयबद्ध तरीके में जांच की अवधियों के लिए बांग्लादेश में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और भारत को एवं अन्य देशों को संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत से संबंधित सारी संगत सूचना दायर की। उन्होंने प्राधिकारी के साथ सहयोग किया और पृथक पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए अनिवार्य सूचना उपलब्ध कराई।
- ii. पूर्ण सहयोग और सारी संगत सूचना को प्रस्तुत करने के बावजूद, प्रकटन विवरण हमारी कंपनी के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों को निर्धारित न करने का प्रस्ताव करता है। प्रकटन विवरण का अवलोकन दर्शाता है कि प्राधिकारी ने दावे के साथ कहा है कि उत्पादक/ निर्यातक की सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत, दोनों से संबंधित सूचना इस आधारभूत कारण से विश्वसनीय नहीं है कि जांच की पी. ओ. आई. एक भविष्य सापेक्ष अवधि थी अथवा आवेदक को पी. ओ. आई. की जानकारी थी हालांकि, हमने कंपनियों द्वारा यथा अनुरक्षित सत्यापित आंकड़े प्रस्तुत किए थे। नई शिपर समीक्षा का प्रयोजन एक नए शिपर को पूर्ववर्ती जांच में दंडात्मक अवशिष्ट शुल्कों के अधीन नहीं लाना है और पृथक पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए एक निर्धारित पी. ओ. आई. में उसके कीमत आचरण को सिद्ध करने का अवसर प्रदान करना है। उत्पादक/ निर्यातक के सामान्य मूल्य/ निर्यात कीमत की इस आधार पर अवहेलना करना एकदम अनुचित होगा कि जांच एक भविष्य सापेक्ष अवधि में की गई थी।
- iii. आवेदकों में "पटसन उत्पादों" थी जोकि उत्पाद था, सत्यापनीय लागत प्रस्तुत की है जो दिनांक 15.07.2019 के इसके प्रमाणपत्र के अनुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सत्यापित किया है कि पी. ओ. आई. के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित लेखे और अन्य लेखे/ वित्तीय रिकार्डों अनुरक्षित किये गये हैं और बी एफ आर एस को अनुसरण में आई सी ए बी द्वारा संदर्भित आई ए एस के अनुसार बांग्लादेश में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में रिपोर्ट किए गए हैं। चूंकि, उत्पादक और निर्यातक ऐतिहासिक रूप से एक विशिष्ट तरीके में अपना डाटा अनुरक्षित करते हैं, वे केवल इस जांच के लिए अपनी लेखाकरण पद्धति में परिवर्तन नहीं कर सकते। आवेदकों द्वारा अनुरक्षित रिकार्ड ऐसे प्रकारवार लागत निर्धारण का अनुसरण नहीं करते और ऐसी प्रकारवार लागत बांग्लादेश में सामान्य कारोबार या कारोबार कानूनों की अनिवार्यता नहीं है। प्रकारवार लागत समुचित समानुपात आधार पर निर्धारित की जाती है जैसे उत्पादन आदि का मूल्य जो कि कई जांचों के लिए अपनायी गयी एक मानक पद्धति है जहां कच्ची सामग्री समान है और तैयार उत्पाद का मूल्य ग्रेडों, गणना आदि के आधार पर भिन्न-भिन्न होता है।
- iv. कंपनियों ने पी. ओ. आई. के दौरान भारत और अन्य देशों को संबद्ध वस्तुओं की उल्लेखनीय मात्रा निर्यातित की हैं। आवेदकों ने अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार काम किया है और संबद्ध वस्तुओं की सत्यापित लागत उपलब्ध कराई है। कीमतें बाजार द्वारा निर्धारित की जाती हैं और ऐसी कीमतों को 'अविश्वसनीय' शब्द प्रदान करना नई शिपर समीक्षा की क्षमता के विरुद्ध जाता है।

ज. प्राधिकारी द्वारा जांच

24. प्राधिकारी ने उत्पादक/ निर्यातक के अनुरोधों में नोट किया है कि नई शिपर समीक्षा जांच में, प्राधिकारी सामान्य मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए भिन्न दृष्टिकोण नहीं अपना सकता। इसके अतिरिक्त, उत्पादक/ निर्यातक ने बेड-लिनेन मामले का उदाहरण दिया है। आवेदक ने यह भी कहा है कि कंपनी यार्न के उत्पादन की गणनावार लागत को अनुरक्षित नहीं करती और यह यार्न की विभिन्न गणनाओं के लिए उत्पादन की औसत लागत उपलब्ध कराता है और यह कि बिक्री मूल्य के आधार पर, विभिन्न यार्नों के उत्पाद की लागत को मूल्यांकित किया जा सकता था। उक्त निवेदनों को नोट करने के पश्चात प्राधिकारी धारित करते हैं कि आवेदक ने इससे इंकार नहीं किया है कि यार्न की भिन्न गणना की कीमत और लागत भिन्न-भिन्न है। प्राधिकारी आगे धारित करते हैं कि ऐसी स्थिति में, जो पी यू सी/ के विभिन्न पी सी एन पर

'एप्पल टू एप्पल' तुलना की मांग करती हैं, प्राधिकारी ने पहले भी ऐसा अभ्यास किया है। पी सी एन स्तर पर सक्षम मूल्यांकन अंत में जहां भी उचित समझा जाए औसत को प्राप्त कर सकता है। बेड-लिनेन मामला पी सी एन स्तर पर तुलना का निषेध नहीं करता। प्राधिकारी यह भी धारित करते हैं कि किसी एन एस आर जांच में, जहां आवेदक पृथक पाटन मार्जिन को स्थापित करने के लिए एक प्रत्याशित अवधि में निर्यात कर रहे हैं, यह अपेक्षाकृत अनिवार्य है कि एक उचित 'एन एप्पल टू एप्पल' तुलना अपनाई जानी चाहिए। वर्तमान मामले में प्राधिकारी ने, यार्न की विभिन्न गणनाओं के बीच कीमत में भिन्नता को नोट करते हुए, आवेदक से यार्न के उत्पादन की गणनावार लागत उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जिसे आवेदक उपलब्ध नहीं करा सका। यह प्राधिकारी को भारत को निर्यातित यार्न की पृथक गणनाओं के लिए सामान्य मूल्य को स्थापित करने से बाधित करता है। प्राधिकारी, यार्न के लिए उत्पादन की गणनावार लागत को निर्धारित करने के लिए आवेदक द्वारा पुनः स्थापित पद्धति को नोट करते हुए धारित करते हैं कि ऐसे परिदृश्य में, जहां, यार्न की कीमत स्वयं में ए डी संवीक्षा के अधीन है, बिक्री कीमत पर उत्पादन की लागत के कुछ भागों को विभाजित करने की पद्धति उचित नहीं है। इसलिए, प्राधिकारी ने यार्न की विभिन्न गणनाओं के लिए सामान्य मूल्य को स्थापित करने में अपनी असमर्थता को दोहराया है जैसा कि प्रकटन विवरण में कहा गया है।

प्राधिकारी ने भारत को पी. ओ. आई. के दौरान यार्न के विभिन्न गणनाओं की निर्यात कीमत के संबंध में आवेदकों के निवेदनों को नोट किया है और इसके सौदावार आयात आंकड़े को साझा करने के अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया। प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया सौदावार आंकड़े डी जी - प्रणाली आंकड़े हैं जिनमें गोपनीय आधार पर आयातक और निर्यातक के नाम प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए हैं। प्राधिकारी ने आंकड़ों की पुनः जांच की है और प्रकटन में दिए गए अनुसार अपने निष्कर्षों की पुष्टि की है। यार्न की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर बांग्लादेश जूट गुड्स निर्यातकों द्वारा किए गए निवेदन केवल उनके द्वारा व्यक्त उचित कीमत से संबंधित राय है न कि किसी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। आवेदक द्वारा भारत को कीमतों की समान गणना की अन्य आयात कीमतों के साथ तुलना की गई है जो वास्तविक सी आई एफ डाटा के अनुसार है और इसलिए, आवेदक द्वारा उत्पादित किसी राय की तुलना में वास्तव में विश्वसनीय है। जहां तक, तुलना के लिए आयातों के सी आई एफ के स्थान पर पहुंच कीमत का संदर्भ देने का संबंध है, यह उचित नहीं है, क्योंकि आवेदक उत्पादक/ निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों को ए डी शुल्क के बिना निर्यातों के रूप में नहीं समझा जा सकता। आवेदक द्वारा किए गए ये निर्यात फिर भी बंधन तहत हैं किंतु अवशिष्ट ए डी डी की देयता के साथ हैं यदि आवेदक के दावों को स्वीकार नहीं किया जाता। अंतिम निर्धारण के बिना लंबित शून्य ए डी डी की कल्पना नहीं की जा सकती। यह तथ्य कि आवेदक उत्पादक/निर्यातक द्वारा निर्यातों के केवल **6.25%** की कीमतें उसी ग्रेड/काउंट अर्थात् 14/1 सैकिंग के लिए जांच अवधि के दौरान अन्य निर्यातकों के साथ तुलनीय हो सकती हैं, दर्शाता है कि आवेदक उत्पादकों/निर्यातकों की निर्यात कीमतें अन्य उत्पादकों/निर्यातकों से अधिक हैं और उन्हें विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। प्राधिकारी ने आवेदक को जांच अवधि के दौरान बांग्लादेश से अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के साथ निर्यात कीमत के अनुसार आगे रैंक किया है ताकि इससे इस बात को और वैध बनाया जा सके जिसमें कि यह स्पष्ट है कि आवेदक की कीमतें काफी उच्चतर बैंड में रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्राधिकारी मानते हैं कि पाटन मार्जिन का मूल्यांकन **5%** के तर्कसंगत लाभ के साथ औसत उत्पादन लागत के रूप में सामान्य मूल्य पर विचार करते हुए किया गया है और कारखाना द्वार निर्यात कीमत विश्वसनीय नहीं होगी और केवल ऐसा प्रतिनिधि अलग-अलग मार्जिन, जिसे आवेदक को प्रदान किया जा सकता हो, मूल जांच परिणाम में यथा-मूल्यांकित गैर प्रतिदर्श श्रेणी का उपाय होगा। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मूल जांच में गैर प्रतिदर्श उत्पादकों/निर्यातकों ने उन्हें प्रदत्त गैर प्रतिदर्श मार्जिन को अनुचित या गैर प्रतिनिधि बताकर उसे चुनौती देते हुए किसी समीक्षा का अनुरोध नहीं किया है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी आवेदक उत्पादक/ निर्यातक के लिए भी जूट यार्न पर उत्पादक/ निर्यातक की गैर-नमूना श्रेणी के उपाय की सिफारिश करते हैं।

झ. निष्कर्ष और सिफारिशें

25. इसलिए प्राधिकारी का मत है कि प्रस्तुत परिस्थितियों और मामले के तथ्यों को देखते हुए, प्राधिकारी मानते हैं कि उत्पादक/ निर्यातक पर केवल ए डी उपायों के लिए विचार किया जाना चाहिए जैसाकि यार्न के लिए मूल जांच में निर्यातकों की नान-सैंपल्ड श्रेणी के लिए सिफारिश की गई है। इसके अलावा, चूंकि, यह उपाय उत्पादक/ निर्यातक के आवेदन पर आधारित है, यह निश्चय ही न्यायोचित और सही होगा। तदनुसार, वर्तमान प्राधिकारी निम्नानुसार सिफारिश करते हैं :-

i) क्रम संख्या 50 पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को सी एन संख्या 11/2017-सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 3.4.2017 में उल्लिखित विद्यमान शुल्क सारणी में सम्मिलित की जानी है जैसाकि सी एन सं. 03/2019-सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 15.01.2017 के जरिए संशोधन किया गया है या अंतिम जांच परिणाम सं. **7/7/2018**-डीजीटीआर दिनांक **19/9/2019** के अनुसार।

क्र. सं.	शीर्ष/उप शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	विशिष्ट विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	यूनिट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
50.	5307, 5310, 5607 अथवा 6305	यार्न	सभी रूपों व विशिष्ट विवरण में	बांग्लादेश	बांग्लादेश	अजीज फाइवर्स लि०	अजीज फाइवर्स लि०	97.19	अमरीकी डालर/ मी. टन

ii) सी एन सं. 42/2018-सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 24.08.2018 के अनुसरण में पी. ओ. आई. अर्थात् 1.7.2018 से 31.3.2019 के दौरान किया गया यार्न के निर्यात को ऊपर (i) के अनुसरण में नियमित किया गया जाना चाहिए। दिनांक 1.7.2018 के पश्चात से मै० अजीज फाइवर्स द्वारा किए गए यार्न के निर्यात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन लाया जाएगा जैसा कि ऊपर (i) में कहा गया है, जो कि सी एन सं. 11/2017-सीमा शुल्क (ए डी डी) दिनांक 3.4.2017 की विद्यमानता के साथ संलग्न होगा।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2019

FINAL FINDING

Subject: New Shipper Review under Rule 22 of Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 pertaining to Anti-Dumping Duty

imposed on the imports of Jute Products” viz – Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian Fabric and Jute Yarn originating in or exported from Bangladesh, as requested by M/s Aziz Fibres Limited (Producer/Exporter), Bangladesh initiated on 2.07.2018.

No. 7/25/2018-DGAD: Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

A. Background of the Case

2. Whereas, in the original Anti-Dumping investigation, the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) recommended, inter alia, imposition of anti-dumping duty on the imports of “Jute products” viz- Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian fabric, and Jute sacking bags, originating in or exported from Bangladesh and Nepal, falling under Chapter 69 of the Customs Tariff Act, 1975, vide Final findings Notification No. 14/19/2015-DGAD dated 20th October, 2016. The Central Government notified the definitive anti-dumping duties vide Notification No. 01/2017-Customs (ADD) -Customs dated 5th January 2017 and Customs Notification No. 11/2017-Cus (ADD) dated 3rd April, 2017.
3. M/s Aziz Fibres Limited (Producer/Exporter), Bangladesh filed an application for New Shipper Review (NSR) in terms of Rule 22 of the Anti-dumping Rules read with the Customs Tariff Act, requesting for a New Shipper Review (NSR) claiming individual dumping margin in respect of imports of the “Jute Products” originating in or exported from Bangladesh wherein AD measure has been imposed on “Jute Products” vide Customs Notification no. 11/2017-Cus (ADD) dated 3rd April, 2017.
4. The Authority, having been prima facie satisfied with the conditions laid down under Rule 22 of Anti-dumping Rules, initiated a New Shipper Review investigation, vide Notification No.7/25/2018-DGAD dated 2nd July 2018, for determination of individual dumping margin for the purposes of imposition of the anti-dumping duties levied on the dumped imports of Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single) Hessian Fabrics and Jute Sacking Bags originating in or exported from Bangladesh, in respect of M/s Aziz Fibres Limited (Producer/Exporter), Bangladesh.
5. Ministry of Finance notified the provisional assessment on all exports of the subject goods made by of M/s Aziz Fibres Limited (Producer/Exporter), Bangladesh till completion of the aforesaid NSR investigation vide Notification No.42/2018-Customs (ADD) dated 24th August, 2018.
6. The period of investigation for the purpose of this New Shipper Review was fixed as 1st July, 2018 to 31st March, 2019.

B. PROCEDURE

7. The procedure described below has been followed with regard to the present investigation:
 - (i) The Authority issued a public notice vide Notification No. 7/25/2018-DGAD dated 2nd July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject NSR anti-dumping investigation.
 - (ii) The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the applicant along with a copy of the exporter’s questionnaire and gave them opportunity to make their views known in writing, and filing relevant data in the prescribed Questionnaire, after expiry of the POI.
 - (iii) The Authority also forwarded a copy of the initiation notification to the High Commission of Bangladesh in India.
 - (iv) The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the known domestic producers in India and gave them opportunity to make their views known in writing.
 - (v) In response to the initiation notification, Questionnaire response was filed, M/s Aziz Fibres Limited (Producer/Exporter), Bangladesh NSR. IJMA representing the Domestic Industry of “Jute Products” in India also filed their representations.
 - (vi) The Authority made available non-confidential version of submissions/ information filed by the interested parties, in the form of a public file, kept open for inspection by interested parties.
 - (vii) The Authority held an Oral Hearing on 8th July, 2019 to provide an opportunity to interested parties to present information orally in accordance with Rule 6(6) followed by written submissions. The interested parties were allowed to present rebuttal rejoinders on the views/information presented by other interested parties. The Authority has considered submissions received from various interested parties appropriately.

- (viii) All relevant Submissions/comments made by interested parties, during the course of this investigation have been considered and included in this disclosure statement.
- (ix) The Authority issued a disclosure statement dated 30th August 2019 to the participating interested parties.
- (x) *** in the statement represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by Authority under the AD Rules.
- (xi) Exchange Rate of Rs. 71.92 per USD has been adopted for POI.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

- 8. The product under consideration in the original investigation is 'Jute Products' comprising of Jute yarn/twine (multiple folded/cabled and single), Hessian Fabrics and Jute Sacking bags. The Authority had recommended separate duty for each type of Jute products in the original investigation to producers. This investigation pertains to the exports of PUC as defined in the original investigation as stated in the initiation notification.
- 9. The present investigation relates to proposed exports of Jute Yarn/twine (multiple folded/cabled and single) (product type under the product under consideration as stated in Final Findings dated 20th October, 2016) by M/s. Aziz Fibre Limited (Producer/Exporter) as per the application filed by them before the Authority in accordance with the Act and the AD Rules.

D. SUBMISSIONS BY VARIOUS INTERESTED PARTIES AND DOMESTIC INDUSTRY :

10. Submissions by the Domestic Industry:

- i. IJMA submits that the applicant sought the present initiation without providing adequate and necessary information and evidence in terms of the Act, the AD Rules and Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade, 1994 ("ADA"), the understanding of the Directorate with regard to new shipper reviews that has prevailed in last five years, and the decisions of the Designated Authority and CESTAT with regard to new shipper.
- ii. Further, till date, petition lacks any information and evidence to "show" that the applicant satisfies the requirements of Rule 22 and therefore, the present investigation must be terminated immediately.
- iii. While a bona fide new shipper has the right to seek individual margins, at the same time, the Designated Authority needs to ascertain that the claims are bona fide and there is no abuse/ misuse/ circumvention of anti-dumping duties. It is for this reason that the applicant needs to be strictly put to establish that (a) they are genuine/bona fide exporters who have made bona fide sales (b) they have not exported goods in the original investigation and (c) they are not related to producer or exporter of subject goods who is attracting anti-dumping. In the instant case the applicant does not fulfil any of the criteria.
- iv. There is nothing in the application which shows that the essential requirements have been fulfilled. As held by the Hon'ble tribunal in the matter of H & R Johnson (India) Limited v. Designated Authority that "The word "show" is not meant to prescribe just a formality of a bare assertion by the applicant that the applicant is not "related".
- v. The applicant has failed to provide evidence that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product, leave aside the evidences to establish the same. The requirement under the law is "to show", i.e., "demonstrate" and not "claim" or "state".
- vi. Web research shows that the said applicant is related to a group which is involved in the production and sale of subject goods. There are several other related parties. These parties have been in existence since decades.
- vii. The applicants sought prospective period as period of investigation i.e., a period which is subsequent period to the initiation of investigation under Rule 22. Reference is made to the decision by Hon'ble CESTAT in Tiles case wherein the concept of prospective POR has been heavily criticized.
- viii. By the reason of prospective period of investigation, the applicants have been able to manipulate and doctor the price by (a) making only ceremonial exports, i.e., 90 MT of exports, (b) at artificially high price. It is pertinent to note here that despite imposition of ant dumping duties, imports from Bangladesh has been significant. However the exporter has chosen to export low volume of subject goods which is insignificant in relation to total imports. It seems from the conduct of the applicant that they are not serious about the fate of the present matter and the current exercise is to merely an attempt to try luck if they can get a favourable margin. Their actions do not indicate that they are serious about exporting their products.

- ix. The applicant has not replied appropriately to the questions on evidence of irrevocable contractual agreements of sales of the product under consideration to India.
- x. The exports made by the applicants during the period of investigation in a new shipper review case must be bona fide commercial transactions of reasonable volume and price to be a basis for a dumping margin. It needs to be seen whether the sales under consideration is typical and will be representative of the new shipper's future sales. If a producer's or exporter's transactions involve price, quantities, and overall circumstances that do call into question the commercial viability of those sales, the genuineness of those sales, both in terms of value and volume, should be examined.
- xi. Other country laws, such as US, Brazil, Canada, EU, Turkey, Taiwan and Vietnam etc are pertinent to note in this regard, which also provides that the transactions undertaken by the exporter should be bona fide and commercial in nature.
- xii. The Authority has specifically prescribed that the quantities exported by the exporter should be in commercial quantity so as to receive an individual margin of dumping. The applicant had argued that the trade notice was issued recently and thus will have effect for future cases, it is submitted that the principle highlighted is not a new principle. The principle of actual exports been made in commercial quantity has been recognized by the Authority as well as Hon'ble CESTAT in past.
- xiii. If an exporter is allowed a margin based only on a small volume of exports or based on an expectation of exports, this would open the scope for manipulation of prices by the exporter for obtaining a lower margin.
- xiv. There is no questionnaire response from the importers of the product under consideration. This further smokes conscious attempt to suppress the fact that a token export was made at unrealistic price in order to obtain a low or no dumping margin and thereafter aggressively dump the volumes
- xv. The applicants have claimed excessive confidentiality without any good cause and for the sole objective of hiding information from the domestic industry and preventing the domestic industry from defending its interests.
- xvi. The applicants have provided no evidence whatsoever to demonstrate how the export price claimed by them is reasonable, reliable, representative and sufficient for the purpose of determination of export price.
- xvii. There is no comparison with the imports into India to demonstrate reliability of the export price.
- xviii. There appears grossly incomplete information with regard to both domestic selling price and cost of production of different types of the product to demonstrate adequacy and sufficiency of information and evidence. Nor the Designated Authority has information on record to account for differences in product types.
- xix. Without prejudice, if the Authority concludes that applicant satisfies the condition and individual duties are justified, it is then submitted that the applicant may be given weighted average duties given to the cooperating companies not included in the sample in the original investigation, since the original investigation involved sampling.
- xx. The domestic industry is additionally concerned for the reason that the domestic industry has sufficient reasons to believe that the quality and quantity of evidence and information provided by the exporters from Bangladesh has always remained a MAJOR ISSUE in all past investigations.

11. Submissions by the Applicant Exporter):

- i. The applicant fulfils the requirements to be treated as a new shipper as stipulated in Rule 22 of the AD Rules which has its basis in Article 9.5 of the WTO AD Agreement. Rule 22 says that the designated authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to India during the period of investigation, provided that these exporters or producers show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product. The applicant meets these requirements.
- ii. It is reiterated that the applicant in the present NSR investigation did not export the subject goods to India during the original POI nor are related, with emphasis to all the connotations of the term 'relation' in the context of an NSR review as stipulated either in the rules or as notified by way of administrative trade notices, to any of the producers or exporters attracting anti-dumping duties on subject goods as notified therein.

- iii. Apart from the submission and certifications to substantiate the conditions of Rule 22, the applicant has submitted detailed documents which cover details and certifications on commencement date of production of subject goods by the company, audited reports and other statutory certifications, details of purchase of plant and equipments etc which will further establish the claims of the new shipper applicant.
- iv. The applicant fully meet the requirements of Rule 22 and further submit that the parties have no intention to dump the material in India and it is very essential to subject their bona fide exports to new shipper review for determination of individual margins based on the facts of actual exports made by them. The applicant has exported significant volume of the subject goods to India during the POI fixed. In case of M/s Aziz Fibres Limited (Producer/Exporter), Bangladesh, the exports of PUC were in the range of 450 to 550 MT.
- v. NSR investigations are integral part of the AD Agreement and also Indian AD Rules and the provision enables a new producer or exporter as defined therein to prove his case as a new exporter which will enable the Authority to examine whether there is any element of dumping in case of exports by such a new exporter. Allegation of IJMA against NSR is not of any basis.
- vi. Neither the Agreement nor the Rule stipulate any specific volume or price of export as a condition for determination of individual margins in an NSR. What makes an unrelated new shipper 'new' is precisely the fact that, during the original investigation period it did not export the subject goods to the territory where the subject goods were subjected to an anti-dumping investigation.
- vii. In fact the WTO Appellate Body clearly held against any laws framed putting in volume requirements in the conduct of a review as per Article 9.5 of the AD Agreement and the decision of the WTO Appellate Body in Mexico – Anti-Dumping Measures on Rice in this regard is binding on the Indian Authority as well read with the judgment of the Hon'ble Supreme Court in GM Exports matter.
- viii. In certain past cases, the Authority declined to grant individual margin to the new exporter as the Authority found the volume of exports by the new exporter as too insignificant to be considered as commercially representative Quantity to be adopted for according individual Dumping Margin to the applicant Producer/Exporter. However, present case shows that the volume in the present case is very significant and the export price concerning such significant volume needs to be treated as inherently reliable.
- ix. The new shipper in the present case meets all the basic conditions as per Rule 22 and also the additional conditions emanated as part of the practices by the Authority in the recent past, both in terms of the requirement of reasonableness of volume and the trustworthiness of the price.
- x. It has been contended by IJMA that the no individual margins should be determined for the new shipper here and in any case it cannot be anything other than the margins applicable on the 'non sampled category of exporters' as found in the original case. The contention has no legal basis. The rule clearly says that the Designated Authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers. It has been clarified by the Authority about its decision to adopt the margin for the non-sampled category in one of the NSRs concerning PUC while publishing the Final Findings concerning Melamine that it was '*constrained by the facts of the case had decided to only accord non-sampled category of AD duty to the applicant*'.
- xi. Any view taken under such constraining scenarios cannot become a rule especially in view of the clear legal position given in Rule 22 which requires the Authority to determine individual margins for the new shippers based on their relevant data.
- xii. The contention of IJMA that present NSR was initiated without adequate evidences to prove the condition of Rule 22 is denied as bereft of any merit. The petition contained evidences to show that the new shipper did not export the subject goods to India during the original POI and the new shipper is not related to any producer or exporter who is attracting ADD. Also, significant time has elapsed since initiation of the present matter and the DI could not produce any piece of evidence to contradict the claims of the applicant.
- xiii. The contention of IJMA qua the prospective POI has no basis. There has been significant number of NSRs initiated and concluded after the Tiles matter wherein the POI was fixed as prospective. The practice of prospective POI is correct in view of the provisions in Rule 22 which says that the Central Government shall not levy anti-dumping duties under sub-section (1) of section 9A of the Act on imports from such exporters or producers during the period of review as referred to in sub-rule (1) of this rule and this rule shall be otiose if the new shipper has to export before initiation of NSR.

- xiv. It has been contended by IJMA that by the reason of prospective period of investigation, the applicants have been able to manipulate and doctor the price by (a) making only ceremonial exports, i.e., 90 MT of exports, (b) at artificially high price. The contention has no basis. The applicant here has exported about 450-550MT (and not 90 MT as contended) of subject good which is a substantial volume and no such substantial export could have been possible at a manipulated price as alleged.
- xv. It has been contended by IJMA that absence of contractual agreement to export to India shows the exporter is not serious. The contention has no basis. Such contractual agreements are not mandatory and such contracts depend on the opportunities for trade. In any case, the exporter has exported about 450-550MT of subject goods which is a substantial volume.
- xvi. It has been contended by IJMA that the exports in NSR review must be a bona fide commercial transaction. It can be noted that the new shipper in the present matter exported significant volume to determine individual margins. This is without prejudice to our submission that the WTO Appellate body in Mexico-Rice matter has clearly ruled that the authorities cannot impose any volume requirements in the conduct new shipper reviews under the aegis of Article 9.5 of the AD Agreement which is the basis of Rule 22 of Indian AD Rules. However, the volume of exports in the present matter invariably fulfils certain parameters put in place by the Authority to examine the reasonableness of exports as evident in some of the recent NSR findings.
- xvii. It has been contended by IJMA that there is no questionnaire response from the importers of the product under consideration and the applicants have claimed excessive confidentiality. Both the contentions have no basis. The importers in the present matter are not related parties of the applicant and the exporter in no way could have acted in a manner to ensure those parties file the IQ Response. The applicant claimed confidentiality as permissible in the Rule. In fact, the parties have given even the range of actual exports so that the DI gets a better idea of the case in hand.
- xviii. It has been contended by IJMA that applicants have provided no evidence whatsoever to demonstrate how the export price claimed by them is reasonable, reliable. The contention has no legal or factual basis. The fact remain the applicant has exported significant quantity to India which itself proves the reasonability of the price. No such exports could have been possible with an artificially inflated price.
- xix. It has been contended by IJMA that importer concerned have not cooperated with the Designated Authority and the Designated Authority cannot verify the information and satisfy itself that there is no compensatory arrangement between the exporter and importer. The contention has no basis. There are many cases concluded by the Authority where the importers did not cooperate but export price claimed by the exporters were verified and accepted. Non-cooperation by the importer no way vitiates the credibility of price claimed by the exporter and there are other mechanisms used to verify the same such as data from customs/DGCI&S etc.
- xx. It has been contended by IJMA that there appears grossly incomplete information with regard to both domestic selling price and cost of production of different types nor the Designated Authority has information on record to account for differences in product types. The contention has no basis. The EQ Response filed by the applicant has all applicable product type information.
- xxi. It has been contended by IJMA that quantity of evidence and information provided by the exporters from Bangladesh has always remained a MAJOR ISSUE in all past investigations. Such assertions have no basis. It is felt that the Authority initiates and conducts an investigation when a case for such an investigation is clearly shown and not merely as alleged.

E. EXAMINATION BY AUTHORITY

12. Rule 22 of the Anti-Dumping Rules provides as follows –

“22. Margin of dumping, for exporters not originally investigated.

(1) If a product is subject to anti-dumping duties, the designated authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to India during the period of investigation, provided that these exporters or producers show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product.

(2) The Central Government shall not levy anti-dumping duties under sub-section (1) of section 9A of the Act on imports from such exporters or producers during the period of review as referred to in sub-rule (1) of this rule:

Provided that the Central Government may resort to provisional assessment and may ask a guarantee from the importer if the designated authority so recommends and if such a review results in a determination of dumping in respect of such products or exporters, it may levy duty in such cases retrospectively from the date of the initiation of the review.”

13. Article 9.5 of the WTO Agreement states as under –

“9.5 If a product is subject to anti-dumping duties in an importing Member, the authorities shall promptly carry out a review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to the importing Member during the period of investigation, provided that these exporters or producers can show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product. Such a review shall be initiated and carried out on an accelerated basis, compared to normal duty assessment and review proceedings in the importing Member. No anti-dumping duties shall be levied on imports from such exporters or producers while the review is being carried out. The authorities may, however, withhold appraisement and/or request guarantees to ensure that, should such a review result in a determination of dumping in respect of such producers or exporters, anti-dumping duties can be levied retroactively to the date of the initiation of the review.”

14. In terms of the aforesaid Rule, provisions in the WTO Agreement and the past practice of DGTR, a New Shipper Review investigation is to be carried out under following circumstances for the purpose of determining individual dumping margin in respect of any exporter or producer from the subject country attracting ADD:

- i. that the exporter or producer has not exported the product under consideration during the period of investigation, and
- ii. that exporter or producer shows that they are not related to any of the exporter or producer in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product concerned.

15. In the instant case M/s Aziz Fibres Limited (Producer/Exporter), Bangladesh has filed an application before the Authority seeking individual dumping margin on “Jute Products” and requested for initiation of the new shipper review.

16. As regards the eligibility of the producer/exporter for claiming ‘NSR’, the Authority has conducted detailed examination of the claims made by the producer/exporter including table study of various documents submitted with respect to data/ information filed by the producer/exporter. Such examinations were conducted in view of the requirements of Rule 22 and the past practices of the Authority. No interested party has provided evidence of non-fulfilment of condition by the producer/exporter for NSR by way of any substantive evidences other than submissions. The Authority therefore proposes to hold that the producer/exporter is eligible to seek a New Shipper Review in the instant case.

F. DETERMINATION OF INDIVIDUAL DUMPING MARGIN FOR THE APPLICANT

i. Overall sales of PUC and non PUI during POI of applicant producer

17. The producer/exporter have produced and sold both PUC (Yarn and Sacking Bag) and Non PUC (sacking cloth) and Hessian Bag during the POI as below:

Particulars	Unit	Yarn
Production	MT	***
Total Sales	MT	***
Domestic Sales	MT	***
Sales to India	MT	***
Sales to 3 rd countries	MT	***

The count wise/variety wise sales details are as under:

Sr. No.	PCN	India			3 rd Countries			Domestic		
		Volume (MT)	Value (BDT)	Price BDT/MT	Volume (MT)	Value (BDT)	Price BDT/MT	Volume (MT)	Value (BDT)	Price BDT/MT
	CB									
1	8 LBS 1 PLY	-	-	-	***	***	***	-	-	-
2	10 LBS 1 PLY	***	***	***	-	-	-	-	-	-
3	20 LBS 1 PLY	***	***	***	-	-	-	***	***	***
4	28 LBS 2 PLY	***	***	***	-	-	-	-	-	-
	Hessian									
5	12 LBS 1 PLY	-	-	-	-	-	-	***	***	***
6	16 LBS 1 PLY	***	***	***	***	***	***	***	***	***
7	20 LBS 3 PLY	***	***	***	***	***	***	-	-	-
	Sacking									
8	14 LBS 1 PLY	***	***	***	-	-	-	-	-	-
9	18 LBS 1 PLY	***	***	***	-	-	-	-	-	-
10	28 LBS 1 PLY	-	-	-	***	***	***	-	-	-
11	28 LBS 3 PLY	-	-	-	***	***	***	***	***	***
	Total	***	***	***	***	***	***	***	***	***

ii. Normal Value

18.

- a. During the table study, the representatives of the company gave details in support of their claim related to major raw-material i.e. Jute purchase register, Production records i.e. Monthly Production reports submitted to Bangladesh Jute Spinners Association (BJSa), copies of VAT Returns, sales records, Audited Accounts of the company for the POI. The practising Chartered Accountant vide its certificate dated 15.07.2019 certified that Audited Accounts of the company for the POI and other Accounts/Financial Records are maintained and reported in accordance with accounting principles generally accepted in Bangladesh as per IASs referred by ICAB following BFRS. The basic records of the producers/exporters were by and large not professionally organised and were of times also in Bangla, and required translation. However, the audited accounts of the POI has been considered as the basis for calculating cost of production as was done in the case of anti-circumvention case of Jute products. The company is only producing Yarn during the POI. The company has not maintained separate accounting/cost records for the different type/ count of yarn (i.e. CB, Hessian & Sacking of different LBS and Ply) being produced by company and there is a variation in the sales prices among the different types of yarns.

- b. During the POI the company has produced *** MT of only Yarn and exported *** MT to India. As the company is producing Yarn, no allocation is required. Therefore, the average cost of production of Yarn after considering bank charges based on Audited Accounts for the POI has been worked out as BDT ***/MT.
- c. The Authority notes that in the original investigation, the methodology adopted for computing 'Normal Value' of Yarn was on weighted average basis including all varieties of Yarn. The original investigation was conducted on a historical POI and opportunity for export price being adjusted for a favourable dumping margin was not available as could happen in a New Shipper Review. Therefore weighted average approach would be largely representative. The instant being a New Shipper Review wherein the Yarn varieties exported to India have different cost and price. Grade wise/count wise cost of production is an important parameter. The Authority notes that keeping in view that no count wise cost for different varieties of Yarn has been provided, it is not possible to compute the cost of production under consideration i.e. Yarn on a count wise/variety wise and apply the OCT test on domestic or for 3rd country exports appropriately as the case may be. The Authority under these constraints is unable to establish a normal value for different variety of Yarns exported to India during the Period of Investigation. The Authority has dealt comments by the applicant producer/exporter and the submissions by the Bangladesh High Commission and Domestic Industry in response to the disclosure statement in the later paras appropriately.

iii. Export Price

19. The Authority reiterates that in the disclosure statement dated 30th August, 2019 it was held that the producer/exporter has exported to India directly. During POI they have exported 16 consignments totalling to *** MT at an invoice value of *** US\$ (*** US\$/MT) (CNF). The adjustments have been claimed on the basis of actual expenses incurred on inland freight, Port expenses and bank charges to an extent of ***, *** and *** \$/MT respectively. Based on the above the average net export price to India has been claimed as US\$ *** per MT.

The Authority notes that the producer/exporter has exported *** MT of Yarn which includes, Hessian and Sacking variety during POI to India. The exports of Yarn by applicant exporter constitutes 1-2% of the total imports from Bangladesh respectively in POI.

The Authority has compared the prices of export of different varieties of Yarn on sample basis to the extent feasible during POI to India by the applicant with other exporters from Bangladesh to check if the export prices of different variety of Yarn of the applicant exporter were realistic. On comparing the export price of two specific types i.e. grade 14/1 sacking varieties of the applicant exporter with other exporters (account for almost 6% of total exports of applicant) it is noted that the export prices of the applicant exporter is higher by 15-20% for this specific grade. For other specific grades comparative data for such a comparison is not available. However, keeping the comparison of two grades as stated above, the Authority does not consider it appropriate to consider the export price of the applicant exporter reliable. The post disclosure submissions of the applicant producer/exporter and domestic industry on consideration of export price are dealt in later paras appropriately.

iv. Dumping Margin

20. The Authority in the view of (iii) and (ii) above is constrained to establish an Individual dumping margin for the PUC under this investigation. The Authority however notes that the applicant producer has provided cost of production on an overall basis. If the weighted average cost of production only for all varieties of Yarn exported to India with appropriate profit of 5% and export price of applicant exporter (appropriately adjusted in view of price variation stated in (iii) above) are compared, Dumping is evident for Yarn. As individual dumping margin cannot be conclusively established, the Authority proposes to consider the non-sampled quantum of measure of the original investigation which is infact an average of different cooperative producers/exporters and in such a case would be representative. The Authority has dealt post disclosure comments by the applicant producer/exporter and also the domestic industry on grant of individual dumping margin to the applicant producer/exporter in the later paragraphs appropriately.

G. Post Disclosure Comments

21. M/s TPM representing the domestic industry submitted the following post disclosure comments:
- i. In NSR investigation it needs to be shown that exports made by the new shipper applicant during the period of investigation in a new shipper review case is bona fide commercial transaction, which is to be the basis for a dumping margin. The purpose was not to "ascertain the fair value of the merchandise but examine each sale for its commercial reasonableness

- ii. Import volume is negligible of total imports. Moreover, the exporter must establish appropriateness and reliability of export price having regard to the export volume. The examination done by the Authority has shown that the export price is not representative
- iii. There is no reason bonafide or otherwise provided by the exporter to show how the exporter has been able to export goods at a higher price than the others when the same type of good is being imported at much lower price.
- iv. Other parameters that can be examined for appropriateness of the export price such as the price at which domestic industry has sold the product under consideration, unless the exporter demonstrates the reasons for differences in prices for different parties, Absence of compensatory arrangements between the importer and its buyer and exporter and importer, price at which the goods have been resold by the importer etc.
- v. Applicants have made no efforts to seek questionnaire response from the importer in India. The importer in India has not come on board in this investigation. In view of no questionnaire response from the importers, the applicant has not established how the Designated Authority can ascertain appropriateness of the import price
- vi. the applicants have provided nothing which can be construed to imply that the applicants have shown to the Designated Authority that they satisfied the requirement under Rule 22

22. M/s M.S. Pothal & Associates representing the exporter/Producer submitted the following post disclosure comments:

A. The grounds for rejection of cost in the context of determination of normal value of the PUC produced by the applicant needs reconsideration as the rejection is not just and fair.

- i. The legal framework of determination of dumping margin for an article exported by the producer or exporter is provided under Section 9A (6A) and rules to enable the process has been framed under Rule 10 by giving effect to Annexure I.

“The designated authority while determining the normal value, export price and margin of dumping shall take into account inter alia, the following principles -

1. The elements of costs referred to in the context of determination of normal value shall normally be determined on the basis of records kept by the exporter or producer under investigation, provided such records are in accordance with the generally accepted accounting principles of the exporting country, and such records reasonably reflect the cost associated with production and sale of the article under consideration”.(Emphasis added)

- ii. The above text of Annexure I to the Anti-dumping Rules clearly has its basis in Article 2.2.1.1 of the WTO Anti-dumping Agreement. While interpreting the requirements of Article 2.2.1.1, the WTO Panel In Egypt – Steel Rebar noted that both Articles 2.2.1.1 and 2.2.2 "emphasize two elements, first, that cost of production is to be calculated based on the actual books and records maintained by the company in question so long as these are in keeping with generally accepted accounting principles but that second, the costs to be included are those that reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration.
- iii. In the present investigation, the applicant has submitted the cost information pertaining to the product under consideration as per the records maintained by the company which is as per GAAP. The Company has no system of maintaining the count wise cost for different varieties of Yarn because such a costing is not part of the normal course of business. Para 17. b. of the Disclosure acknowledges that the applicant is a producer of single type of PUC which is Jute Yarn and the cost of the same was available. Para 17.c. in the Disclosure statement as reproduced above nowhere says that the applicant failed to show that their cost records are maintained as per GAAP or any element of costs do not reflect the cost associated with the PUC which is Yarn (Jute Products) in terms of any particular element of cost. Further please note that company produces yarn of three varieties namely CB, Hessian and Sacking, within these three varieties there are number of counts in each of three varieties, and in counts there are number of plies, hence for a small scale company it is not viable to maintain type wise raw material cost for each of the PCNs. The observation is only that it is not possible to compute the cost of production of different types of yarn on count wise/variety wise as the count wise costing is not provided. This cannot be a fair ground for the rejection of cost concerning PUC.
- iv. As the applicant has provided the cost for PUC which is Yarn here, the observation that the relevant cost for PUC is not available needs reconsideration though at later part in the Disclosure the Authority noted that the applicant has provided weighted average cost for the PUC. As far as cost of different types of yarn is concerned, the applicant

suggested that the main cost is on account of raw materials and the cost of raw material could have been allocated based on sales value ratio concerning different types of yarn. This is based on the principle that the product which has a higher realization in the market has a higher cost as well. Such a method is reasonable and could have enabled the Authority to determine even the type wise cost of yarn though the requirement of Rule is to determine the cost for the PUC and not for its *inter se* types. Without prejudice, type wise cost of yarns on the above basis is enclosed.

- v. The applicant in the context of type wise cost also submits that Annexure II to the WTO AD Agreement clearly addresses a situation where the information provided may not be ideal in all respects at para 5 of Annexure II. Absence of type wise cost needs to be seen in this context. The Agreement clearly says that even though the information provided may not be ideal in all respects, this should not justify the authorities from disregarding it, provided the interested party has acted to the best of its ability. In the present case, the applicant has acted to best of its ability as the applicant has provided cost as per its records at PUC level and also provided type wise cost on a proper allocation basis. The determination of cost on a type wise basis could be a matter of allocation and a pragmatic and normally followed methodology for the same was also suggested.
- vi. Notwithstanding the above, the moot question which emanates from the observation of the Authority in para 17.c. is that can the Authority adopt a different approach in the determination of cost of the article under investigation in the context of normal value in a New Shipper Review for the primary reason that POI of the present NSR is a prospective period which is known to the applicant at the time of exports or the investigation in question is a new shipper review?. Our respectful submission is that such an approach has no legal sanctity and the methodologies provided in Annexure I are applicable in every determination of dumping margin be it a fresh investigation or new shipper review. Also, the nature of investigation per se which is NSR here does not vitiate or prejudice the reasonableness of cost in any manner nor nature of investigation can be a ground to dispute the reasonableness of cost. Nature of review cannot be a ground per se to determine the reasonableness of cost and reasonableness of cost has to be examined based on reasonableness of various elements of cost involved in the claims of the applicant and cannot be merely on a presumptive basis citing the nature of investigation. It is respectfully submitted that such a view goes against the purpose of new shipper review as envisaged in Article 9.5 of the AD Agreement and such a view can seriously prejudice the rights of the applicant and the prospective POI in the present case was determined by the Authority as permissible under the law. Once the POI is determined as permissible in the law, the same cannot be a ground to doubt the credibility of cost and price claimed by the applicant and such a presumption goes against the premises of present initiation. It is requested that the normal value may kindly be determined based on principles envisaged in Annexure I to the Rules viz. determination of cost in the context of normal value like any AD investigation and an NSR applicant should not be placed on a different pedestal while determining his cost.
- vii. It is also submitted that the requirement under the law is to determine dumping margin for the product under consideration and not type wise and in that context, disregarding the cost of PUC which is as per the records maintained by the company based on GAAP is not justified at all. In EC – Bed Linen, the WTO Appellate body found as follows;

"53. We see nothing in Article 2.4.2 or in any other provision of the Anti-Dumping Agreement that provides for the establishment of 'the existence of margins of dumping' for types or models of the product under investigation; to the contrary, all references to the establishment of 'the existence of margins of dumping' are references to the product that is subject of the investigation. Likewise, we see nothing in Article 2.4.2 to support the notion that, in an anti-dumping investigation, two different stages are envisaged or distinguished in any way by this provision of the Anti-Dumping Agreement, nor to justify the distinctions the European Communities contends can be made among types or models of the same product on the basis of these 'two stages'. Whatever the method used to calculate the margins of dumping, in our view, these margins must be, and can only be, established for the product under investigation as a whole. We are unable to agree with the European Communities that Article 2.4.2 provides no guidance as to how to calculate an overall margin of dumping for the product under investigation" (Emphasis added)
- viii. Thus, absence of type wise/count wise cost maintained by the applicant for the inter se types of the PUC cannot be a ground to reject the cost of the PUC as maintained by the applicant. Had the applicant failed to submit the cost of PUC as per the two main requirements i.e records as per GAAP and reasonableness of cost as provided in the Rule, it would have been a different issue. In the present case, the applicant has provided required data as per the Rule to determine normal value and the rejection of cost for the grounds given therein are not justified at all and we crave before the Authority to reconsider the same in the interest of justice and fairness.

B. The grounds for rejection of export price as claimed the applicant needs reconsideration as the rejection is not just and fair.

- i. As a primary submission, it is reiterated that the applicant has exported significant volume of subject goods and no such volume level could have been possible at a price unreasonably higher than the prevailing market price. The applicant exported at a price comparable to the prevailing market prices and it was no way an inflated price.
- ii. The comparison of export price of the applicant with some exports made by the other exporters as a sample is not a fair method to check the reliability of the export price of the applicant as the sample selected is not representative at all in terms of volume and level of trade. The applicant vide its letter dated 1.9.2019 requested for the entire data of exports of PUC from Bangladesh for a proper comparison but the same is not provided. Any such comparison has to be on a reasonable basis and the sample selected here are miniscule. Until and unless, the export price of the applicant is compared to a significant portion of total export of the same kind of PUC from Bangladesh to India during the POI made by other exporters, no fair view can be arrived without any distortion in the approach.
- iii. The export price as relied upon by the Authority in the corroborative sample appears to be at CIF level and not at landed level. The PUC is attracting ADD for majority of the exporters and any price comparison needs to be made by taking such duty into consideration. The applicant exported the PUC subject to the present review and no ADD was applicable on such PUC at the time of imports. Thus, the import price of an importer importing from an exporter in the residual category of exporter, who got the lowest duty and exporter with no duty cannot be compared at the same breadth. The element of duty clearly comes in the price at the end of the importer and any comparison has to be made at the landed level to see what the actual price of imports was. Hence, the observation that the price of the applicant was 15-20% higher and hence not reliable needs reconsideration based on facts of trade.
- iv. It is to be noted here that the applicant also exported the subject goods to India in the Post POI period. The post POI imports do not have any bearing on the determination of dumping margin and even the price during Post POI reflects such level of prices which is comparable to the prices in POI. It may be please be noted that the company has exported substantial quantity in the post POI period which also shows the reliability and consistency of price. We request the Authority to consider post POI price of export also to examine the veracity of export price claimed by the applicant for the POI. The price during the post POI would clearly show that the allegation of exporter inflating the price to get a lower margin is completely baseless.
- v. We are further enclosing a circular issued by Bangladesh Jute Mills Corporation, wherein it can be seen that the price for CB 10 LBS/1 Ply is listed as *** US\$ per MT as international export price. Our price during POI was BDT *** which is equal to US\$ *** per MT. It can be seen that our price is comparable to Govt. decided price. The relevance of this circular is that though such prices are not strictly binding as a bench mark, such prices clearly indicated the price range prevailing in the market and the applicant also exported at a realistic price comparable to such notified price to India. It cannot be said that the applicant exported at an unrealistic price not at par with what other exporters were considering.
- vi. We are further enclosing a letter issued by Bangladesh Jute Goods Exporters' Association, wherein they have disclosed the international price of 14/1 and 28/1 sacking quality yarns, this price also matches our export price during the POI. This is also indicative of the fact that the applicant was not exporting at any artificial prices to India and such prices were very prevalent in the market parlance.
- vii. Thus, based on the above it is submitted that the view of the Authority on the export price claimed by the applicant as proposed in the Disclosure needs reconsideration based on facts and we crave for the same in the interest of justice and fairness.

C. The applicant could provide verifiable information for the purpose of determination of individual dumping margin in case of its exports to India. Any proposal for an alternate methodology should be seen in this context.

- i. Rule 22 of Anti-dumping Rules governing New Shipper Reviews clearly says *the designated authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers*. The requirement is clearly determination of individual dumping margins and it cannot be adaptation of some other margins determined in the past or for some other parties.
- ii. It is also respectfully submitted that the Authority has in a recent NSR concerning Janata Jute Mill NSR case concerning the same PUC had determined Individual Margin based on margins for non sampled category. However, the Authority clarified its position on the said determination on the course of an eventual investigation concerning

Melamine as follows; *“The Authority notes that in the same determination the Authority had emphasised the need to establish reasonableness and credibility of export price and constrained by the facts of the case had decided to only accord non-sampled category of AD duty to the applicant.*

- iii. Thus, the adaptation of margin for the non-sampled category in the Janata Jute Mill_case was the result of certain factual constraints in the said case and there are no such constraints in the present matter. The applicant has provided details to determine individual dumping margin and the exports by the applicant were substantial during the POI. Any view taken under some constraining scenarios in some other cases cannot become a rule especially in view of the clear legal position given in Rule 22 which requires the Authority to determine individual margins for the new shippers based on their relevant data. Neither the Rule nor the anti-dumping Agreement provides for any provision which enables the Authority to adopt a margin for the NSR applicant other than that of the individual margin based on its own data like margin of the non-sampled category of exporters in the original case.
- iv. Without prejudice, it is our respectful submission that the Authority shall be in a position to determine individual margin for the applicant and there shall be no need to adopt any other basis or adoption of best available information after proper consideration of these comments. The applicant would like to draw the attention of the Authority to Article 6.8 of the Anti-Dumping Agreement which allows investigating authorities to make determinations on the basis of facts available only in such cases where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information, or significantly impedes the investigation. None of the above conditions is applicable to the NSR applicant as the applicant have fully cooperated with the Authority and were willing to provide any other information that may be required by the Authority. Following WTO decisions are relevant in this regard;
 - a. In Argentina – Ceramic Tiles, the Panel held that "It is clear to us, and both parties agree, that an investigating authority may disregard the primary source information and resort to the facts available only under the specific conditions of Article 6.8 and Annex II of the AD Agreement. Thus, an investigating authority may resort to the facts available only where a party: (i) refuses access to necessary information; (ii) otherwise fails to provide necessary information within a reasonable period; or (iii) significantly impedes the investigation."
 - b. In US – Steel Plate, the Panel analyzed the extent of the limitation that paragraph 3 of Annex II puts on investigating authorities' right to reject information submitted and instead resort to facts available and did not accept the United States' position that 'information' in Article 6.8 means all information, such that Members have an unlimited right to reject all information submitted in a case where some necessary information is not provided.
 - c. The Panel in EC - Salmon (Norway) drew support from US – Hot-Rolled Steel and US – Steel Plate held that "Paragraph 3 of Annex II directs investigating authorities to take all submitted information into account for the purpose of its determinations when it is: (i) 'verifiable'; (ii) 'appropriately submitted so that it can be used in the investigation without undue difficulties'; (iii) 'supplied in a timely fashion'; and, where, applicable, (iv) 'supplied in a medium or computer language requested by the authorities'. Thus, paragraph 3 of Annex II calls upon investigating authorities to take into account all information that satisfies three, or sometimes four, cumulative conditions when making determinations. It follows that where all of the conditions are satisfied, an investigating authority will not be entitled to reject information submitted when making determinations."

23. Comments to disclosure filed by Bangladesh High Commission:

- i. The three companies concerned filed all relevant information pertaining to Normal value of subject goods in Bangladesh and Export price of subject goods to India and to other countries for the period of Investigation in the prescribed Exporter Questionnaire Response format and in timely manner. They cooperated with the Authority and provided with necessary information for determination of individual dumping margin.
- ii. Despite full cooperation and submission of all relevant information, the Disclosure statement proposes not to determine normal values and export prices for our company. A perusal of the Disclosure statement shows that the Authority asserted that information pertaining to both normal value and export price of the producer/exporter are not reliable for the fundamental reason that the POI of the investigation was a prospective period or the applicant had the knowledge of the POI though we submitted verifiable data as maintained by the companies. The very purpose of the new shipper review is not to subject a new shipper to punitive residual duties in an earlier investigation and to provide an opportunity to prove his price behaviour in a prescribed POI for determination of individual margin of dumping. Therefore it would be a very unfair to disregard the normal value and export price of the producer/exporter on the ground that the investigation was done in a prospective period.

- iii. The applicants have submitted verifiable cost of the “jute products” which was the product Chartered Accountant vide its certificate dated 15.07.2019 certified that Audited Accounts of the company for the POI and other Accounts/Financial Records are maintained and reported in accordance with accounting principles generally accepted in Bangladesh as per IASs referred by ICAB following BFRS. Since the producers and exporters maintain their data in a particular manner historically, they could not have changed their accounting methodologies only for this investigation. The records maintained by the applicants do not follow such type wise costing and such type wise cost is not a requirement of general business or business laws in Bangladesh. The type wise cost could have been determined based on a proper apportionment basis such as value of production etc. which is a standard method adopted for many investigations where the raw materials are same and the value of end product varies depending upon the grades, counts etc.
- iv. The companies had exported significant quantities of the subject goods to India and to other countries during the POI. The applicants have acted to the best of their ability and provided verifiable cost of the subject goods. The prices were driven by the market and merely terming such prices as unreliable goes against the spirit of New Shipper Reviews.

H. Examination by Authority

24. The Authority notes the submissions of the producer/exporter that in a new shipper review investigation the Authority cannot adopt a different approach to evaluate normal value. Further, the producer/exporter has cited the bed linen case. The applicant has also stated that company does not maintain count wise cost of production of yarn and that it has provided the average cost of production for different counts of yarn and that based on sales value, cost of product of different yarns could be evaluated. The Authority after noting the above submissions holds that the applicant has not denied that price and cost of different count of yarns vary. The Authority further holds that in situations which warrant an apple to apple comparison at different PCN's of PUC, the Authority has undertaken such an exercise in past. The granular evaluation at PCN level may ultimately be averaged out wherever considered appropriate. The bed linen case does not prohibit a PCN level comparison. The Authority also holds that in a NSR investigation where the applicant is exporting in a prospective period to have an individual dumping margin established, it is rather imperative that fair comparison at apple to apple be undertaken. The Authority in the instant case, noting the price variation amongst different counts of yarn, requested the applicant to provide count wise cost of production of yarn which the applicant could not provide. This constrained the Authority to established the normal value for different counts of yarn exported to India. The Authority, noting the methodology reiterated by the applicant to determine count wise cost of production for yarn, holds that in a scenario where the prices of yarn itself are subject of AD scrutiny, methodology to apportion some parts of cost of production on the sales price is not appropriate. Therefore, the Authority reiterates its inability to establish normal value for different counts of yarn as stated in the disclosure statement.

The Authority notes the submissions of applicants regarding export price of different counts of yarn during POI to India and its request to share the transaction wise import data adopted by Authority. The Authority clarifies that transaction wise data considered by Authority is DG-Systems data wherein the name of importer and exporter is available to the Authority on a confidential basis. The Authority has revisited the data and confirms its observation as given in the disclosure. The submission by the Bangladesh Jute Goods Exporters Association on international prices of yarn are merely opinions of reasonable price expressed by them and are not supported by any evidence. The prices to India by the applicant are compared with other import prices of same count which are as per the actual CIF data and therefore are infact credible rather than an opinion produced by the applicant. As regards referencing landed price instead of CIF of imports for comparison, the same is not appropriate as exports by the applicant producer/exporter cannot be considered as exports without an AD duty. These exports made by applicant are nevertheless under bond but are with a liability of residual ADD if applicant claims are not accepted. There cannot be an assumption of nil ADD pending a final determination. The fact that only prices of 6.25% of exports by applicant producer/exporter could be compared with other exporters for same grade/count i.e. 14/1 sacking during the POI, indicates that export prices of applicant producer/exporter are higher than other producers/exporters and can not be considered reliable. The Authority has further ranked the applicant in terms of export price with other producers/exporters of Bangladesh during the POI to further validate from wherein it is evident that prices of the applicant are in the much higher band. Under such circumstances, the Authority holds that the dumping margin evaluated considering normal value as average cost of production with 5% reasonable profit and the ex-factory export price would not be reliable and the only representative individual margin that can be accorded to the applicant is the non-sampled category of measure as evaluated in the original finding. The Authority also notes that the non-sampled producers/exporters in original finding have not requested for any review of the non-sampled margin accorded to them challenging them as not being appropriate or non-representative.

The Authority in view of the above, recommends measure of non-sampled category of producer/exporter on Jute Yarn for the applicant producer/exporter as well.

I. Conclusions and Recommendations

25. The Authority therefore holds that in the given circumstances and facts of the case, the producer/exporter can only be considered for an AD measure as recommended for the non-sampled category of exporters in original investigation for Yarn, which would indeed be fair and appropriate. Accordingly the Authority recommends as under:

- i. Following entries at S. No. 50 be added to the existing duty table mentioned in C.N. No. 11/2017-Customs (ADD) dated 3/4/2017 as amended through C.N. No. 03/2019-Customs (ADD) dated 15/1/2019 or in accordance with Final Finding No. 7/7/2018-DGTR dated 19/9/2019.

S. No.	Heading/ sub heading	Description of Goods	Specification	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Duty amount	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
50.	5307, 5310, 5607 or 6305	Yarn	In all forms and specification	Bangladesh	Bangladesh	Aziz Fibres Limited.	Aziz Fibres Limited.	97.19	US\$/MT

- ii. Export of yarn made during POI i.e. 1/7/2018 to 31/3/2019 in accordance with the C.N. No. 42/2018-Customs (ADD) dated 24/8/2018 be regularised in accordance with (i) above. To further clarify the export of yarn made by M/s Aziz Fibres Limited. w.e.f. 1/7/2018 will be subjected to AD duty as stated in (i) above which would be conterminous with the existence of C.N. No. 11/2017-Customs (ADD) dated 3/4/2017.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General